

जयपुर टाइम्स

राजस्थान की रंग-रंग से निकली बात
जयपुर टाइम्स मैगजीन के साथ



राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी





भजनलाल शर्मा के रोड शो से पूरे प्रदेश में

04

भजनलाल शर्मा के रोड शो से पूरे प्रदेश में खुलकर खिला "कमल का फूल"



सेना, खेल और राजनीति तीनों में डंका

11

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सेना, खेल और राजनीति तीनों क्षेत्र में बजाया अपने नाम का डंका



मथुरा के लाल का राज. में कमाल

18

श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के एक और "लाल" का राजस्थान में कमाल



अपर्णा आरोड़ा के कुशल प्रबंधन और नवाचारों

22

अपर्णा आरोड़ा के कुशल प्रबंधन और नवाचारों से खान विभाग में एक अच्छे अध्याय की शुरुआत



आईएस राजेश यादव गांव से जुड़ी समस्या

28

गांव से जुड़ी समस्याओं और विकास को बेहतर तरीके से समझने वाले आईएस "राजेश यादव"



सिंधम लेडीज नम्रता का माफिया पर चाबुक

35

सिंधम लेडीज आईएस नम्रता वर्षिनी का खनन माफिया पर चाबुक, सरकारी राजस्व को चोट पहुंचाने वालों की खैर नहीं



बजरी माफिया के जानी दुश्मन आईपीएस वर्मा

41

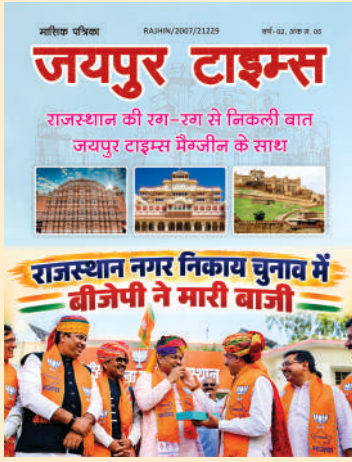
बजरी माफिया, नशे के कारोबारी और गैंगस्टर के जानी दुश्मन तो युवाओं के जानी दोस्त आईपीएस "राजर्षि राज वर्मा"



मानवता की मिशाल है एडवोकेट कुड़ी

46

सालों से वकीलों के कुनबे में मानवता की मिशाल बने सीनियर एडवोकेट "मोहन कुड़ी"



प्रकाशक, मुद्रक
रामेश्वर लाल जाट

संपादक
नीतू चौधरी

उप संपादक
कुमकुम रंगा, रूपचंद
गुर्जर, रोहित शर्मा

ग्राफिक डिजाइनर
रजत जाखड़

स्वत्वाधिकारी

केम्ब्रिज मल्टी मीडिया
के लिए प्रकाशक, मुद्रक
रामेश्वरलाल जाट द्वारा
केम्ब्रिज मल्टी मीडिया प्रा.लि.
सी-565, सी-4सी स्कीम,
न्यू लोहा मण्डी रोड़, सीकर
रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं
सी-565, सी-4सी स्कीम,
न्यू लोहा मण्डी रोड़,
सीकर रोड़ जयपुर से प्रकाशित

संपर्क

संपादक

जयपुर टाइम्स (मासिक)
सी-588, सी-4सी स्कीम,
न्यू लोहा मण्डी रोड़
जयपुर-302013

E-mail

jaipurtimes2007@gmail.com

website

www.jaipurtimes.org

मो. 7014217770

मूल्य:- 100/- प्रति अंक

वार्षिक सदस्यता- 1251 (पोस्टल चार्ज सहित)

सुधी पाठकों के लिए जयपुर टाइम्स का विशेष संदेश

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल, पारदर्शिता से ही दूर होगा भ्रम

तथ्यों, दस्तावेजों और स्पष्ट जवाबों से ही कायम

रह सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का भरोसा

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव आयोग केवल चुनाव कराने वाली एक प्रशासनिक संस्था नहीं है। निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव व्यवस्था में जनता के विश्वास की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी इसी संवैधानिक संस्था पर है। राजनीतिक दल चुनाव जीतते और हारते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के प्रति नागरिकों का भरोसा कायम रहना लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। इसलिए, जब स्वयं चुनाव आयोग के भीतर लिए गए फैसलों को लेकर गंभीर सवाल सार्वजनिक चर्चा का विषय बनें, तो उनका जवाब तथ्य, दस्तावेज और पारदर्शिता के साथ सामने आना लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में है। हाल में प्रकाशित एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने लगभग दस महीनों के दौरान कम-से-कम 14 मौकों पर आयोग के विभिन्न कदमों को लेकर आपत्तियां या टिप्पणियां दर्ज कीं। इनमें मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़े विषय भी बताए गए हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने इन खबरों के बाद स्पष्ट किया कि आयोग के अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए और चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियां निर्णय लेने की सामान्य विचार-विमर्श प्रक्रिया का हिस्सा थीं। यही अंतर अब सार्वजनिक बहस का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। एक तरफ मीडिया रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों का उल्लेख है और दूसरी तरफ आयोग का कहना है कि अंतिम निर्णय सर्वसम्मति थे। दोनों बातें एक साथ संभव भी हो सकती हैं। किसी विषय पर विचार-विमर्श के दौरान सदस्य प्रश्न उठा सकते हैं, किसी प्रक्रिया में सुधार सुझा सकते हैं और बाद में संशोधन के बाद अंतिम निर्णय से सहमत हो सकते हैं। इसलिए, केवल आंतरिक आपत्ति दर्ज होने से यह निष्कर्ष निकाल लेना उचित नहीं होगा कि आयोग का अंतिम फैसला अनिवार्य रूप से असहमति के बावजूद किया गया। लेकिन, ठीक इसी कारण पूरी तस्वीर स्पष्ट होना आवश्यक हो जाता है। मामला किसी सामान्य सरकारी विभाग से जुड़ा होता, तो संभवतः कुछ दिनों बाद विवाद समाप्त हो जाता। लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका अलग है। मतदाता सूची में किसका नाम रहेगा, किसका हटेगा, चुनाव कब होंगे, चुनाव आचार संहिता कैसे लागू होगी और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगी—इन सभी विषयों पर आयोग के निर्णय सीधे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े हैं। इसलिए, आयोग के संबंध में पैदा हुआ भ्रम भी साधारण प्रशासनिक भ्रम नहीं माना जा सकता। यहां स्पष्टीकरण मांगने का अर्थ किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार या अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों के बारे में केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि आयोग उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट करे कि जिन 14 आपत्तियों या टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है, उनका स्वरूप वास्तव में क्या था। क्या वे नीतिगत असहमतियां थीं? क्या वे तकनीकी सुझाव थे? क्या संबंधित फैसलों में बाद में परिवर्तन किया गया? और, यदि अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से हुए, तो पहले उठाए गए सवालों का समाधान किस प्रकार किया गया? इस तरह का विस्तृत स्पष्टीकरण स्वयं चुनाव आयोग के हित में होगा।

यदि प्रकाशित रिपोर्ट में किसी तथ्य को

गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, तो आयोग को उसका स्पष्ट, बिंदुवार और दस्तावेज आधारित खंडन करने का पूरा अधिकार है। बल्कि, संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला होने के कारण तथ्यात्मक गलती होने पर उसका खंडन सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनना उपयोगी होगा। केवल यह कह देना कि सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से हुए, एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, लेकिन सार्वजनिक बहस में उठाए गए अलग-अलग बिंदुओं का उत्तर सामने आने से भ्रम और कम हो सकता है। और, यदि कुछ मामलों में दोनों चुनाव आयुक्तों ने वास्तव में गंभीर प्रक्रियागत आपत्तियां उठाई थीं, तब यह स्पष्ट किया जा सकता है कि उनका समाधान आयोग की संस्थागत प्रक्रिया के भीतर किस तरह हुआ। असहमति अपने आप में किसी संस्था की कमजोरी नहीं होती। वास्तव में, किसी बहुसदस्यीय संस्था में अलग-अलग मत सामने आना स्वस्थ विचार-विमर्श का हिस्सा हो सकता है। इस संदर्भ में चुनाव आयोग की संवैधानिक संरचना भी समझना आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया था कि बहुसदस्यीय चुनाव आयोग में अन्य चुनाव आयुक्त केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के अधीनस्थ अधिकारी नहीं हैं। आयोग सामूहिक संस्था के रूप में कार्य करता है और कानून के अनुसार, जहां सर्वसम्मति संभव न हो, वहां बहुमत से भी निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए, चुनाव आयुक्तों द्वारा किसी विषय पर सवाल उठाना अपने आप में असामान्य या अवैध स्थिति नहीं है।

असल प्रश्न यह है कि संस्थागत प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं और अंतिम निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या थी।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव आयोग पहले ही अपना प्रारंभिक पक्ष सामने रख चुका है। इसलिए, यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि आयोग ने इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी है। आयोग का पक्ष है कि अंतिम फैसले सर्वसम्मति से हुए और आंतरिक टिप्पणियों को अंतिम असहमति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। अब सार्वजनिक विश्वास की दृष्टि से अगला प्रश्न यह है कि क्या इस स्पष्टीकरण को और विस्तार से, संबंधित मुद्दों और प्रक्रिया के साथ सामने रखा जा सकता है। चुनाव आयोग जैसी संस्था के लिए पारदर्शिता का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि चुनाव संबंधी विवादों में

राजनीतिक दल अपने-अपने दृष्टिकोण से आरोप और बचाव करते हैं। मौजूदा विवाद में भी विपक्षी दलों ने रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की आलोचना की है, जबकि भाजपा ने आयोग के भीतर हुई चर्चा को लोकतांत्रिक विचार-विमर्श बताते हुए उसका बचाव किया है। लेकिन, चुनाव आयोग की संस्थागत विश्वसनीयता किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आयोग का सबसे प्रभावी उत्तर वही हो सकता है, जो सत्यापन योग्य तथ्य और आधिकारिक रिकॉर्ड सामने रखे।



—प्रधान संपादक
रामेश्वरलाल जाट

भजनलाल शर्मा के रोड शो से पूरे प्रदेश में खुलकर खिला "कमल का फूल"



प्रदेश में 309 नगर निकायों में 200 से ज्यादा नगर निकायों पर कब्जा करके सत्तारूढ़ भाजपा ने आगामी पंचायत राज और 2028 में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव में दे दिए हैं अपनी शानदार जीत के संकेत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो से पार्टी के चुनाव प्रचार को मिली जबरदस्त नई ऊर्जा और ताकत। बरसात के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सड़कों पर उतरता देख छोटे बड़े शहरों की जनता भी शासन के मुखिया को सैल्यूट करने के लिए हो गई मजबूर, मुख्यमंत्री के रोड शो पर फूलों की बरसात वोटों में हुई तब्दील, तो भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत।

जयपुर। प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए 309 नगर निकाय चुनाव के नतीजे आगामी पंचायत राज और 2028 में प्रदेश में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत की ओर इंगित करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों के चेहरों पर चिंता की लकीर साफ दिखने भी लगी है। क्योंकि नगर निकाय चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस के

अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा और प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल की तरह मान रहे थे, और अपने भाषणों में भी इससेमीफाइनल की जंग में खुद की जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन चुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी के अनुमान के खिलाफ आए, जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं को आत्म मंथन के लिए मजबूर कर रहे हैं। हालांकि, प्रदेश में सत्ता और संगठन से जुड़े लोग शुरू से ही नगर निकाय चुनाव में अच्छी सफलता मिलने की बात कह रहे थे। प्रदेश सरकार के पिछले ढाई साल के कार्यकाल के ऐतिहासिक विकास कार्यों और पानी, बिजली, कृषि, उद्योग, युवा और महिलाओं के विकास के लिए कई बड़े-बड़े निर्णय और जनकल्याणकारी योजनाएं लागू किए जाने से भारतीय जनता पार्टी के नेता नगर निकाय चुनाव में शानदार जीत की बात पहले से ही कह रहे थे। लेकिन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यह भी जानते थे कि नगर निकाय चुनाव में थोड़ी सी लापरवाही और मिस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने समय रहते ही नगर निकाय चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। चाहे पार्टी के उम्मीदवारों के चयन करने की बात हो, या फिर चुनाव प्रचार के तरीकों और चुनाव प्रचार में पार्टी की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों, इन तमाम तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री शर्मा काफी गंभीर दिखे। और उन्होंने पार्टी के संगठन से जुड़े नेताओं, विधायकों, सांसदों तथा जनप्रतिनिधियों, विधानसभा के पार्टी के प्रत्याशियों और नगर निकाय चुनाव के संबंध में दिल्ली से आए पार्टी के नेताओं के साथ रोजाना लगातार बैठके आयोजित करके नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करते रहे, और बिना कोई देरी किए खुद चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान की सड़कों पर अपने रोड शो के माध्यम से उतर गए, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार को जबरदस्त रफ्तार और संबल



मिला। जो नेता पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे थे, या फिर जो नेता पार्टी से नाराज चल रहे थे, उन नेताओं पर भी मुख्यमंत्री के रोड शो ने काफी प्रभाव डाला, और उनमें अधिकांश पार्टी के साथ जुड़ गए। इसलिए, सेमीफाइनल की इस जंग में भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह से पराजित करके आगामी पंचायत राज और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता शायद यह सोच रहे थे कि पिछले 35 साल से राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है, इसलिए 2028 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन, नगर निकाय चुनाव के यह नतीजे कहीं ना कहीं इस बार हर 5 साल में सरकार बदलने की अवधारणा को झूठा साबित कर सकते हैं, इस बात को राजनीतिक विश्लेषक भी स्वीकार कर रहे हैं।

प्रदेश में ढाई साल में छोटे-बड़े शहरों में व्यापक रूप से हुए विकास कार्यों ने भाजपा की जीत में अच्छी भूमिका निभाई

जानकार लोगों का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं, पिछले ढाई साल में प्रदेश में छोटे और बड़े शहरों में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से विकास कार्य और परियोजनाएं धरातल पर संपादित हुई हैं। चाहे परिवहन व्यवस्था हो, या फिर जयपुर जैसे बड़े शहर में मेट्रो के सेकंड फेज के शुरू करने की बात हो, या फिर शहरी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और इनके समुचित विकास करने की बात हो, या फिर पानी, सफाई, सीवरेज, बिजली, सड़क, शिक्षा, पर्यावरण, चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की बात हो, या फिर प्रदेश में ढाई साल में कई बार नगर निकायों में विशेष शिविर आयोजित करके लोगों की समस्याओं के निस्तारण करने की बात हो, या फिर ओवर ब्रिज, हाईवे, पुल निर्माण और पार्कों के सौंदर्यकरण की बात हो, हर क्षेत्र में सरकार ने काफी बढ़िया काम किया। जिसका सीधा अच्छा असर शहर में रहने वाले लोगों के दिलों दिमाग पर भी पड़ा, जिसकी वजह से नगर निकाय चुनाव में शहर की जनता ने सरकार के विकास कार्यों पर अपनी मोहर लगाकर भाजपा को शानदार जीत दिलवाई। इसमें कोई संदेह नहीं, पिछले ढाई साल में प्रदेश भर में हर जिले में रीको की ओर से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहे हैं, जिसमें राइजिंग राजस्थान में हुए समझौते के तहत उद्योगपति अपनी इकाइयां भी स्थापित करने में व्यस्त हैं। इन कार्यों को शहर की जनता ने अपनी आंखों से देखा है। इसी तरह से, पानी के क्षेत्र में कई बड़े समझौते होने से लोगों को लगने लगा है कि उन्हें अब पीने का पानी समुचित रूप से मिल सकेगा। इसी तरह से, बिजली उत्पादन में राजस्थान अच्छी पोजीशन में है, इसलिए ढाई साल में शहरी जनता को बिजली के लिए भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। बड़े स्तर पर शहरी क्षेत्र के युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार भी मिल रहा है। यह तमाम बातें हैं, जिन्हें शहर की जनता ने देखा भी है और महसूस भी किया है। इसीलिए, नगर निकाय चुनाव में शहर के लोगों ने दिल खोलकर भाजपा को वोट किया।

भजनलाल सरकार के पिछले ढाई साल के विकास कार्यों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता



यह तो हर किसी को मानना ही पड़ेगा कि प्रदेश में भजनलाल सरकार के ढाई साल के शासनकाल में हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए। पानी, बिजली, सौर ऊर्जा, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, पर्यटन, पर्यावरण, युवा और महिला विकास जैसे बड़े क्षेत्र में सरकार ने ऐतिहासिक काम किया। बिजली उत्पादन में राजस्थान की स्थिति ढाई साल में काफी अच्छी हुई है, और जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि पिछले 4 महीना से हम दूसरे राज्यों को बिजली बेचने लगे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह पहला मौका है जब राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है। इसीलिए, पानी के क्षेत्र में भजनलाल सरकार की ओर से किए गए निर्णय और फैसला जग जाहिर है। इसी तरह से, राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के समझौते में से 9 लाख करोड़ से ज्यादा के समझौते धरातल पर आ गए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश भर में हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, रोजगार के अवसर डेवलप हो रहे हैं, युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर रोजगार मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने युवा नीति तैयार की है, जिसके माध्यम से युवाओं को 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक का लोन फ्री में रोजगार के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसका युवा अच्छा फायदा उठा रहे हैं। इसी तरह से, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। किसानों के लिए भजनलाल सरकार की ओर से कई तरह के बड़े कदम उठाए गए हैं। किसान सम्मान निधि की राशि में भजनलाल सरकार ने अपने स्तर पर बढ़ोतरी करके किसानों को राहत प्रदान की है, तो दूसरी तरफ किसानों को सहकारिता के माध्यम से लोन उपलब्ध करवाया जा

रहा है। हर तरह की सुविधा कृषक को दी जा रही है। कृषक को खेती के अलावा अन्य सहायक उद्योग धंधों से भी जोड़ा जा रहा है, पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, डेरी सेक्टर, मधुमक्खी पालन जैसे सहायक उद्योग धंधों में कृषक को जोड़ा जा रहा है, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसके अलावा, सोलर प्लांट के माध्यम से कृषक अब अपने खेतों में बिजली उत्पादन भी करने लगे हैं। यह तमाम क्रांतिकारी परिवर्तन पिछले ढाई साल के शासनकाल में प्रदेश की जनता को देखने को मिले हैं। इसीलिए, नगर निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को जी भर कर वोट किया।

आखिरकार अशोक गहलोत को भी भजनलाल शर्मा के रोड शो के जलवे को स्वीकार करना पड़ा

नगर निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान शुरू में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के विभिन्न शहर में रोड शो आयोजित करके पार्टी का माहौल तैयार कर रहे थे, उस समय राजस्थान कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेता मुख्यमंत्री शर्मा के रोड शो पर सवाल खड़े कर रहे थे, और आरोप लगा रहे थे कि अगर प्रदेश में ढाई साल में सरकार ने कुछ काम किया होता, तो आज इस तरह से मुख्यमंत्री को रोड शो आयोजित करने नहीं पड़ते। प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब किसी मुख्यमंत्री ने नगर निकाय चुनाव में इस तरह से व्यापक रूप से रोड शो आयोजित किए हो। इस तरह की बातें कहकर अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटसरा और टीकाराम जूली जैसे बड़े नेता मुख्यमंत्री शर्मा के रोड शो पर कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन, चुनाव के नतीजे के बाद अब प्रदेश में तीन बार शासन की बागडोर हाथ में लेने वाले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अशोक गहलोत खुलकर कह रहे हैं कि अगर भजनलाल शर्मा की तरह कांग्रेस पार्टी के नेता भी इसी तरह से प्रदेश में रोड शो आयोजित करते, तो पार्टी का माहौल और अच्छा होता और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होता। यानी अशोक गहलोत, जो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो पर सवाल खड़े कर रहे थे, वह अब मुख्यमंत्री शर्मा के रोड शो को भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं।

मुख्यमंत्री बनने के बाद भी खुद को भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता मानते हैं भजनलाल शर्मा



राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भजनलाल शर्मा की लाइफ स्टाइल और व्यवहार में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया, और वह अब भी खुद को भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता मानते हैं। उनकी यही हैबिट उन्हें भाजपा के संगठन से जुड़े नेताओं में अपने आप ही बड़ा नेता बना देती है। हालांकि, मुख्यमंत्री बनने से पहले भजनलाल शर्मा प्रदेश भाजपा के 20 साल तक महामंत्री रहे, और करीब आधा दर्जन प्रदेश भाजपा के अध्यक्षों की टीम में रहकर पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाई। इस दौरान, भजनलाल शर्मा प्रदेश भर के संगठन से जुड़े नेताओं को समझने में भी सफल रहे। एक तरफ प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में भाजपा की वस्तु स्थिति को समझने में सफल रहे, तो दूसरी तरफ प्रदेश भर में संगठन से जुड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों के आचरण व्यवहार और कार्य शैली से भी काफी परिचित रहे। क्योंकि 20 साल तक एक ही पार्टी में लगातार प्रदेश महामंत्री पद पर बने रहना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन भजनलाल शर्मा ने अपनी मेहनत और लगन से प्रदेश महामंत्री के काम को शानदार तरीके से संपादित किया, जिस पर गृहमंत्री अमित शाह की भी कड़ी नजर रही, और भजनलाल शर्मा की इस मेहनत के प्रतिफल के रूप में ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान किया गया। लेकिन, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी भजन लाल शर्मा लगातार पार्टी के संगठन से जुड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों से संवाद करते रहते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर लगातार पार्टी के संगठन और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करना उनकी हैबिट बन गई है, तो दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित होने वाली हर छोटी बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा हर हाल में, चाहे कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, जो यह दिखाता है

प्रदेश के सभी नगर निगम में बेहतरीन फील्डिंग सजाकर कांग्रेस के विकेट टपकाए, 10 में से 9 में भाजपा के महापौर

प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के जब नतीजे आए, तो यह किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भाजपा प्रदेश के 10 नगर निगम में से 9 में अपना महापौर बिठा देगी। क्योंकि 10 में से जयपुर, उदयपुर, कोटा और भीलवाड़ा नगर निगम में जरूर भाजपा को बहुमत मिल गया था, बाकी आधा दर्जन नगर निगम में कहीं पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर थी, तो कहीं पर निर्दलीयों की जबरदस्त उपस्थिति थी। इसलिए, राजनीतिक विश्लेषक भी यह मान रहे थे कि मुश्किल से भाजपा 5 या 6 नगर निगम में ही अपना महापौर बन पाएगी। लेकिन, इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चतुर राजनीति और कुशल रणनीति ही कहेंगे कि भाजपा 10 में से 9 नगर निगम में अपना महापौर बिठाने में कामयाब हो गई। जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी, वहां पर मुख्यमंत्री शर्मा की कुशल रणनीति और बेहतरीन तरीके से सजाई गई फील्डिंग से कांग्रेस के विकेट उड़ते गए, और भाजपा वहां पर अपना महापौर बनाने में सफल हो गई। सिर्फ बीकानेर के अलावा सभी जगह पर भाजपा ने नगर निगम में अपने मेयर बना दिए, जबकि अजमेर और पाली में कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा पार्षद चुने गए थे। लेकिन, इन दोनों नगर निगम में भी मुख्यमंत्री शर्मा ने कुशल रणनीति तैयार करके भाजपा के महापौर बिठा दिए। दूसरी तरफ जोधपुर, जहां पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के 44-44 पार्षद चुने गए थे, जोधपुर जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला और गढ़ माना जाता है, जहां से अशोक गहलोत कई बार सांसद रहे हैं और कई बार विधायक रहे हैं, वहां पर महापौर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी, जो अशोक गहलोत के काफी नजदीकी थे, वह भाजपा के प्रत्याशी से चुनाव हार गए, जिसे अशोक गहलोत की सीधी पराजय भी माना जा रहा है। ऐसा ही हल कांग्रेस का कोटा नगर निगम में हुआ। कोटा में शांति धारीवाल कांग्रेस का काफी बड़ा चेहरा माने जाते हैं, लेकिन इस बार नगर निगम के चुनाव में यहां कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा।

कि वह पार्टी के संगठन को सत्ता से भी ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए, प्रदेश भर के संगठन से जुड़े नेताओं का विश्वास और भरोसा हासिल करने में भजनलाल शर्मा पिछले ढाई साल में पूरी तरह से सफल हो गए हैं, और जो नेता पहले भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज थे, वह भी आज मुख्यमंत्री शर्मा के के काफी करीब और नजदीक आ गए हैं। यही वजह रही कि नगर निकाय चुनाव में पार्टी में किसी भी तरह के असंतोष और अंतर विरोध की स्थिति नेताओं में देखने को नहीं मिली, जिसकी बदौलत भाजपा को शानदार सफलता मिली।

तो क्या 35 साल से हर 5 साल में सरकार बदलने के सिस्टम को तोड़ देंगे भजनलाल शर्मा?



प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार सफलता के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलने की प्रक्रिया को इस बार तोड़ पाएंगे? क्योंकि नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी भी इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देख रही थी। वर्ष 2028 के चुनाव से पहले नगर निकाय चुनाव में जो शानदार सफलता भाजपा को मिली है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा ने सेमीफाइनल तो शानदार तरीके से जीत लिया है, और अब फाइनल में भी इसी तरह से जीत की उम्मीद लगाई जा सकती है। हालांकि, फाइनल से पहले कुछ दिनों के बाद प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं, और हाल ही में दादिया में आयोजित

नगर निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण में भरोसा भी जाते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास और भरोसा है कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में भी प्रदेश की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। अगर पंचायत राज चुनाव में भी नगर निकाय चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलती है, तो फिर निश्चित रूप से वर्ष 2028 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव, जो एक तरह से फाइनल मैच के समान होगा, उसमें भी भाजपा की शानदार जीत की संभावना ज्यादा प्रबल हो जाती है। और अगर 2028 में भी भाजपा को विधानसभा चुनाव में सफलता मिलती है, तो फिर निश्चित रूप से पिछले करीब 35 साल से हर 5 साल में प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों की सरकार बदलने की जो प्रक्रिया लगातार चली आ रही है, वह टूट जाएगी, और प्रदेश में दोबारा से भाजपा की सरकार का गठन हो जाएगा। फिलहाल यह तो आने वाला समय बताया कि वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को बहुमत मिलता है। लेकिन, जिस तरह की तैयारी, जो रणनीति नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में तैयार की, उसके बाद भाजपा को शानदार सफलता मिली, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2028 के विधानसभा चुनाव को जीतने में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। अभी सरकार के करीब 2 साल से ज्यादा का समय बाकी है, इसलिए इन 2 साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की जनता का विश्वास और भरोसा हासिल करने के लिए विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री शर्मा लगातार यह दावा भी करते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में किए गए वादों में 78 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए गए हैं। इसके अलावा, राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किए गए सभी बजट की घोषणाओं को पूरा करने में भी भजनलाल सरकार समर्पित भाव से काम करते हुए दिख रही है। इसलिए, अब राजनीतिक विश्लेषक भी यह विश्लेषण करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार हर 5 साल में सरकार बदलने के सिस्टम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं।

नगर निकाय चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव संबंधी सभी विषयों पर मुख्यमंत्री ने रखी कड़ी नजर



राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यह अच्छी तरह से जानते थे कि शासन का मुखिया होने के नाते नगर निकाय चुनाव के नतीजे उनकी पर्सनल राजनीतिक छवि से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री शर्मा नगर निकाय चुनाव को शुरू से ही काफी गंभीरता से ले रहे थे। वैसे भी, मुख्यमंत्री शर्मा मुख्यमंत्री बनने से पहले करीब 20 साल तक राजस्थान भाजपा के लगातार महामंत्री रहे, इसलिए पार्टी के संगठन से जुड़े तमाम विषयों के बारे में उन्हें बहुत अच्छी समझ पहले से ही थी। इसलिए, नगर निकाय चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया से लेकर पार्टी के चुनाव प्रचार के तरीके, और चुनाव प्रचार में पार्टी की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों और विषयों, इन सबको लेकर उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ मंत्रणा करके सुनियोजित तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। जिसमें इस बार नगर निकाय चुनाव में प्रदेश भाजपा की ओर से टिकट वितरण में काफी सावधानी बरती गई। जिताऊ और सक्रिय नेता को ही टिकट देने की दृढ़ इच्छा शक्ति प्रकट की गई, और सिफारिश के आधार पर बहुत ही कम टिकट इस बार भाजपा की ओर से दिए गए। हालांकि, पार्टी ने टिकट वितरण के लिए अलग-अलग

जिलों और अलग-अलग नगर निकायों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी थी, तथा दिल्ली से आए पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी टिकट वितरण के प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखे हुए थे। लेकिन, इन सब के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रत्येक नगर निकाय में टिकट वितरण की प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखे हुए थे, और लगातार यही देख रहे थे कि टिकट वितरण की व्यवस्था पारदर्शक, स्पष्ट और साफ सुथरी हो, ताकि टिकट वितरण के बाद अनावश्यक विवाद की स्थिति पैदा ना हो। हालांकि, टिकट वितरण के बाद प्रदेश भाजपा में कुछ जगहों पर असंतोष और विवाद की स्थिति भी पैदा हुई, लेकिन लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था का यह भी एक हिस्सा होता है। क्योंकि भाजपा दुनिया की नंबर वन विशाल पार्टी है, इसलिए टिकट वितरण में अगर कहीं पर असंतोष और विवाद की स्थिति बनती है, तो कोई अचरज का विषय नहीं होता। लेकिन, मुख्यमंत्री शर्मा ने रोड शो के बाद अलग-अलग जगह पर पार्टी के संगठन से जुड़े नेताओं के साथ बाकायदा मीटिंग आयोजित की, और पार्टी से नाराज होकर चुनाव लड़ रहे लोगों को वापस पार्टी से जोड़ने के लिए गंभीरता से प्रयास करने को भी कहा, जिसके अच्छे नतीजे भी सामने आए। इसलिए, कई बागी उम्मीदवारों ने पार्टी के समर्थन में नाम भी वापस लिए। इस तरह से, नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री के कुशल प्रबंधन और निर्देशन ने पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका अदा की है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शर्मा शुरू से ही पार्टी जनों को कई बार कह चुके थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता अलग-अलग बयान बाजी और अनर्गल विषय उठाकर प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए, कांग्रेस पार्टी के दुष्प्रचार से लोगों को बचाने के लिए भाजपा के जनप्रतिनिधियों और संगठन से जुड़े नेताओं को ज्यादा से ज्यादा फील्ड में लेकर लोगों के साथ संवाद करते रहना है, और केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार की योजनाओं को उपलब्धियां के बारे में लगातार लोगों को जानकारी देते रहना है, ताकि कांग्रेस के दुष्प्रचार से प्रदेश की जनता प्रभावित न हो सके। इसलिए, मुख्यमंत्री शर्मा ने खुद भी रोड शो के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच जाकर लोगों को सरकार के कामकाज और विकास कार्यों की जानकारी देने, तथा कांग्रेस के दुष्प्रचार से बचने की शानदार पहल की, जिसके अच्छे नतीजे भी सामने आए, और भाजपा ने 309 में से 200 से ज्यादा नगर निकायों में जीत दर्ज करके कांग्रेस को जोरदार पटकनी दी।

जल के क्षेत्र में 50 से 60 साल पुराने मामलों का निस्तारण करके प्रदेश के लोगों का जीता दिल



इस बात को सब मानते हैं कि पिछले ढाई साल में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जल के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक और उत्कृष्ट कार्य किए हैं, वे प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गए हैं। पिछले ढाई साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने विवेक और बुद्धि कौशल से, केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन से, विभिन्न राज्यों के साथ जल बंटवारे को लेकर कई सालों से जो विवाद की स्थिति बनी हुई थी, उन विवाद को दूर किया। जिसकी वजह से प्रदेश के अनेक जिलों के लोग जो पानी के लिए तरस रहे थे, अब उन्हें इन समझौते की वजह से समुचित पानी मिल सकेगा। सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार से रामसेतु जल लिंक परियोजना को लेकर जो समझौता किया है, उसे करीब 18 से 20 प्रदेश के जिलों के लोगों को पीने का पानी और खेती का पानी मिलेगा। यह परियोजना करीब 1 लाख करोड़ रुपये की है, जिसमें 42000 करोड़ रुपये के कार्य इस समय प्रदेश में संपादित हो रहे हैं। इसी तरह से, यमुना जल समझौते के तहत चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले के लोगों को पानी मिलेगा। यह समझौता भी पिछले कई सालों से हरियाणा सरकार से लंबित चल रहा था, जिसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समाधान किया। इसी तरह से, नर्मदा परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और निर्देशन में समझौता किया, जिसकी वजह से प्रदेश के लोगों को नर्मदा नदी का पानी पीने को मिलेगा। इसी तरह से, पिछले दिनों छह राज्यों के साथ मुख्यमंत्री शर्मा ने किसानों की परियोजना को लेकर दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में समझौता किया, इससे भी राजस्थान को पीने का पानी मिलेगा। इस तरह से, पिछले ढाई साल में पानी के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने प्रयासों से चार बड़े समझौते किए, जिनकी वजह से प्रदेश के कई जिलों में पीने के पानी और खेती की पानी की समस्या का समाधान होगा। जानकार लोग यह भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री शर्मा ने कम से कम 50 और

60 साल से चले आ रहे इन मुद्दों पर हाथ डाला, और इन्हें सुलझाने का प्रयास तो किया, जबकि इससे पहले प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने इन बड़ी-बड़ी जल बंटवारे की योजनाओं के समाधान के लिए ज्यादा सक्रियता और गंभीरता नहीं दिखाई। जिसकी वजह से प्रदेश में पीने के पानी और खेती के पानी की समस्या कई जिलों में बनी रही, लेकिन अब ढाई साल में पानी के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शर्मा ने जो ऐतिहासिक फैसला किया, उन्हें शहर की जनता ने भी अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि, दिल्ली में जब समझौते होते हैं, तो वे सिर्फ कागजी और दिखावा नहीं होते, उनका अपना वजूद और मतलब होता है, इस बात को सब समझते हैं। यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव में प्रदेश में करीब करीब सभी छोटे-बड़े शहरों में मुख्यमंत्री शर्मा ने पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए जो कठिन मेहनत और प्रयास किया है, उसी की बदौलत शहर की जनता ने भाजपा को लगने का चुनाव में अच्छा वोट दिया।

केंद्र सरकार से प्रदेश के विकास के लिए बड़े स्तर पर सहयोग और आर्थिक मदद हासिल करने में भजनलाल शर्मा पूरे देश में रहे अव्वल

राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भजन लाल शर्मा प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश के विकास के लिए हर तरह से सहयोग और आर्थिक मदद लेने में सबसे ज्यादा कामयाब रहे। भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे पर बार-बार सवाल खड़े करते रहे, और हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते की बात कहकर भजन लाल शर्मा पर बार-बार तंज भी कसते रहे, लेकिन प्रदेश की जनता ने भी यह देखा और महसूस किया कि मुख्यमंत्री शर्मा जब-जब दिल्ली गए, तब तक प्रदेश के विकास के लिए कुछ ना कुछ लेकर लौटे। इसलिए, मुख्यमंत्री शर्मा के बार-बार दिल्ली दौरे को लेकर भले ही कांग्रेस के नेता हायतोबा मचाते रहे, लेकिन प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री शर्मा कि इस कठिन मेहनत और परिश्रम की प्रशंसा करते रहे। और जब दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह के नए प्रोजेक्ट और परियोजनाएं शुरू होती, तो प्रदेश के छोटे बड़े शहर के लोगों का विश्वास भजनलाल शर्मा के प्रति और मजबूत और पक्का हो जाता, जो बाद में नगरनिकाय चुनाव में भी देखने को मिला, जब शहरी जनता ने बीजेपी को जमकर वोट दिया।

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सेना, खेल और राजनीति तीनों क्षेत्र में बजाया अपने नाम का डंका



प्रदेश भाजपा में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इकलौते ऐसे नेता माने जाते हैं, जिन्होंने एक नहीं तीन प्रमुख क्षेत्र मिलिट्री, खेल और राजनीति में अपना और परिवार का नाम रोशन करते हुए राजस्थान और भारत का गौरव भी बढ़ाया। राजस्थान के ऐसे वीर सपूत बने, जिन्होंने कारगिल युद्ध में हिस्सा तो लिया ही और 2004 में भारत की आजादी के बाद ओलंपिक में भारत को पहली बार मेडल दिलवा कर विदेश की धरती पर भारत का राष्ट्रीय गीत बजवाया। अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी की प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रदेश की भजनलाल सरकार का यह श्रेष्ठ मंत्री पूर्व में मोदी सरकार में भी केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी वर्किंग स्टाइल और कामकाज से प्रधानमंत्री मोदी को कर चुका है प्रभावित।

जयपुर। प्रदेश भाजपा ही नहीं, बल्कि राजस्थान की राजनीति में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अकेले ऐसे नेता हैं, जो एक नहीं बल्कि तीन प्रमुख क्षेत्र सेना, खेल और राजनीति में खुद को साबित करके बताया। राठौर एक ऐसी शख्सियत मानी जाती हैं, जिन्होंने भारतीय ओलंपिक इतिहास में भारत को आजादी के बाद ओलंपिक में मेडल दिलवा कर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया। राठौर ने मिलिट्री में अपनी सेवाओं के दौरान अपनी वीरता और साहस से सीमा पर दुश्मन देश की मिलिट्री के जवानों के दांत खट्टे किए, तो कारगिल युद्ध में भी अपने साहस का परिचय देकर खुद का और राजस्थान का नाम रोशन किया। इसलिए वर्ष 2013 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से पहले ही, कर्नल राज्यवर्धन सिंह

राठौड़ राजस्थान और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुके थे। इसीलिए वर्ष 2014 में भाजपा ने जब इन्हें जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, तो लाखों वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे, और इनकी पॉलिटिक्स में दमदार और शानदार एंट्री को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह देकर इनका सम्मान बढ़ाया। बाद में केंद्र में मंत्री रहने के दौरान भी राठौर ने अपनी वर्किंग स्टाइल और कामकाज से पीएम मोदी को काफी प्रभावित किया, और आज राजस्थान में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी अपने कामकाज और वर्किंग स्टाइल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को काफी प्रभावित किए हुए हैं। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का अब तक का अपना जो जीवन रहा है, ऐसा सफल और गौरावित जीवन मुश्किल से बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है, क्योंकि ज्यादातर ग्रेट पर्सनालिटी सिर्फ एक विशेष क्षेत्र से ही जुड़ी होती हैं। लेकिन कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक नहीं बल्कि तीन क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके खुद को साबित करके दिखाया, जो अपने आप में इन्हें एक उच्च कोटि की अलग श्रेणी के रूप में परिभाषित करता है।

पहले लोकसभा और फिर राजस्थान विधानसभा में दमदार तरीके से हुई एंट्री



वर्ष 2013 में मिलिट्री से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और अगले साल वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जयपुर ग्रामीण जैसी बड़ी लोकसभा सीट से भाजपा का उम्मीदवार बना दिया। यहां अपने पहले ही चुनाव में राठौर ने कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 3 लाख 33 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर दमदार तरीके से लोकसभा में पहुंचे, और जहां पीएम मोदी ने इन्हें इनकी अच्छी विकट्री और इनकी पर्सनालिटी से प्रभावित होकर इन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में रहने के दौरान इन्होंने अपने कामकाज और वर्किंग स्टाइल से पीएम मोदी और भाजपा हाई कमान से जुड़े सभी बड़े नेताओं को काफी प्रभावित किया। इन्हें केंद्र सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय जैसे विभाग में काम करने का मौका दिया गया, जो अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी थी। बाद में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें दोबारा से जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। यहां इस बार इनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कृष्णा पूनिया से था, जो राठौर की तरह ही डिस्कस थ्रोअर खेल में देश और दुनिया में अपना नाम कमा चुकी थी, और राठौर की तरह ही खेल जगत में काफी प्रसिद्ध थी। शायद कांग्रेस

पार्टी के रणनीतिकारों ने खिलाड़ी के सामने खिलाड़ी उतार कर मैच जीतने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन कांग्रेस की यह रणनीति सफल नहीं हुई, और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में वर्ष 2019 के चुनाव में ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते। राठौर ने कृष्णा पूनिया को करीब 4 लाख वोटों के अंतर से पराजित किया। इस तरह से अपने राजनीतिक जीवन के शुरू के दो बड़े चुनाव शानदार तरीके से जीतने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने इन्हें राजस्थान में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया। जहां कांग्रेस के स्टैंडिंग मा लालचंद कटारिया जैसे बड़े नेता, जो पिछली गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में पोस्टेड थे, इसलिए इस सीट पर चुनाव जीतना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ा चैलेंज था। क्योंकि एक तरफ कैबिनेट मंत्री के रूप में लालचंद कटारिया ने झोटवाड़ा में काफी विकास कार्य करवाए थे, और यहां जाट समाज के मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं, कटारिया राजस्थान के जाट समाज के बड़े लीडर माने जाते हैं। लेकिन वर्ष 2023 के चुनाव में कटारिया झोटवाड़ा की जगह आमेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, झोटवाड़ा से चुनाव लड़ने से उन्होंने साफ मना कर दिया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने झोटवाड़ा से युवा जाट नेता अभिषेक चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के इस सीट से विधायक रहे राजपाल सिंह शेखावत जैसे नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, तो दूसरी तरफ राज्यवर्धन सिंह राठौर का विधानसभा का यह पहला चुनाव था, इसलिए उनके सामने बड़ी चुनौती थी। क्योंकि अभिषेक चौधरी भले ही झोटवाड़ा से ताल्लुक नहीं रखते हो, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति और एनएसयूआई में उनका अच्छा वर्चस्व था। इसलिए चुनाव प्रचार में बड़ी संख्या में अभिषेक चौधरी के साथ युवा ब्रिगेड मैदान में मोर्चा संभाले हुए थी। इन तमाम बड़ी चुनौतियों के बावजूद भी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने करीब 50000 वोटों से ज्यादा के अंतर से कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक चौधरी को पराजित किया। इस तरह से कर्नल राठौड़ लगातार अपने राजनीतिक जीवन का तीसरा चुनाव भी शानदार तरीके से जीत गए। बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन्हें अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, और कई बड़ी विभागों की जिम्मेदारी इन्हें दी गई।

विधायक बनने के पहले दिन से ही झोटवाड़ा के विकास के लिए समर्पित भाव से कर रहे कार्य



झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद पहले ही दिन से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपना ज्यादातर समय झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण में ही बिताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इनके पास कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी है, इसलिए इनके कंधों पर सरकारी काम बहुत ज्यादा है। इनकी काबिलियत और अनुभव को देख कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन्हें उद्योग और कई अन्य बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी हुई है। इसलिए विभागों के कामकाज का नियमित रूप से अपडेट लेना, और विभागों के कामकाज और मॉनिटरिंग के लिए जयपुर के अलावा प्रदेश में अन्य जिलों के दौरे पर जाना भी इनकी दिनचर्या का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए राठौर पूरी निष्ठा और समर्पित भाव से काम करते हुए दिख रहे हैं। पिछले सवा दो साल में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने खुद की पार्टी की सरकार होना और खुद के कैबिनेट मंत्री पद के होने का जबरदस्त फायदा उठाते हुए व्यापक पैमाने पर विकास कार्य करवाए हैं। एक तरफ विधानसभा चुनाव में जनता से किए वादों को

पूरा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट में भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए अच्छा पैसा स्वीकृत करवाने में काफी कामयाब हुए हैं। इसीलिए क्षेत्र की जनता इन्हें अब झोटवाड़ा के विकास पुरुष के रूप में उपाधि देने लगी है। राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानते हैं कि पिछले 2 साल में झोटवाड़ा में जो विकास कार्य हुए हैं, उनसे झोटवाड़ा क्षेत्र की जनता का अब पहले की तुलना में राठौर से ज्यादा आकर्षक बड़ा है। राठौर अब यहां पहली बार के विधायक के रूप में नहीं लगते, बल्कि इन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से नियमित रूप से जन संवाद और मुलाकात का जो कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, उसकी वजह से झोटवाड़ा क्षेत्र में हर जाति और बिरादरी के लोगों में इनकी पापुलैरिटी अब देखते ही बनती है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े स्थानीय नेताओं से भी लगातार बातचीत करते रहते हैं। लगातार उन्हें अपने आवास पर बुलाकर उनके साथ मीटिंग आयोजित करके, क्षेत्र की समस्याओं और कार्यकर्ताओं की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करके उनके निदान का प्रयास करते हैं। उसकी वजह से झोटवाड़ा क्षेत्र के भाजपा के संगठन से जुड़े छोटे-बड़े सभी नेताओं में भी राठौर अब एक सर्वमान्य भाजपा के नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं। अभी वर्तमान सरकार के ढाई साल से ज्यादा का समय बाकी है, ऐसे में झोटवाड़ा क्षेत्र के लोगों को यह उम्मीद है कि आने वाले ढाई साल भी झोटवाड़ा के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रोजाना कहीं ना कहीं झोटवाड़ा क्षेत्र में विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और क्षेत्र के लोगों से उनकी समस्याएं और विकास कार्यों के बारे में उनके सुझाव और सलाह भी ले रहे हैं। और लोगों के सुझाव और सलाह के आधार पर झोटवाड़ा में विकास कार्यों को गति दे रहे हैं, जो स्थानीय लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इसलिए चर्चा यह भी हो रही है कि हो सकता है राज्यवर्धन राठौर झोटवाड़ा से अपनी कोई एक लंबी राजनीतिक पारी खेलने की योजना बना रहे हो।

"राइजिंग राजस्थान" ऐतिहासिक कार्यक्रम में पहले दिन से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर कर रहे काम

जानकार लोगों का कहना है कि प्रदेश में पिछले सवा दो साल में भजनलाल सरकार की ओर से कई बड़े ऐतिहासिक निर्णय और विकास कार्य किए गए, जिसमें भजनलाल सरकार के कार्यकाल के प्रथम साल में ही राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, सौर ऊर्जा, पर्यटन, खनन, बिजली जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 35 लाख करोड़ रुपए के समझौते किए गए, जिसमें अब तक 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते धरातल पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में एक शानदार और अच्छा माहौल बनने लगा है। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा देश और दुनिया के निवेशक यहां पर अपने उपक्रम स्थापित करें, इस दिशा में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार में अपने पूर्व के मंत्री पद के अनुभव का यहां राजस्थान में उद्योग मंत्री के रूप में बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। चाहे उद्योग नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की बात हो, या फिर देश और विदेश के इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान से कैसे जोड़ा जाए, या फिर राइजिंग राजस्थान में भारी संख्या में हुए समझौते के धरातल पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, किस तरह की कोशिश की जाए, क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इन सबको लेकर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बातचीत करते रहते हैं। और राइजिंग राजस्थान में हुए प्रत्येक समझौते के क्रियान्वयन के लिए उद्योग मंत्री होने के नाते, लगातार सतत प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में अब तक राइजिंग राजस्थान के समझौते धरातल पर आ चुके हैं। रोजाना कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में समझौते करने वाले उद्योगपति को उपक्रम स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित की जा रही है, और देश और दुनिया के निवेशकों को यहां औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए बिल्कुल भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़े, इसके लिए उद्योग मंत्री होने के नाते राठौर खुद पैनी नजर रखते हैं। और अगर किसी को भी, किसी भी तरह से नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने में कोई परेशानी होती है, तो उस मामले

को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत करके तुरंत शॉट आउट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि प्रदेश में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम बनाकर नहीं रह जाए, बल्कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का असर प्रदेश के औद्योगिक ढांचे पर नजर आए। इसलिए मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने शासनकाल के पहले ही साल में इस तरह का बड़ा कार्यक्रम आयोजन करवाया, ताकि कार्यक्रम में होने वाले प्रत्येक समझौते को अपने कार्यकाल में ही धरातल पर उतारा जा सके। क्योंकि मुख्यमंत्री शर्मा और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यह पहले से ही जानते थे कि राजस्थान में पिछली सरकारों ने भी इस तरह का आयोजन करवाया था, लेकिन इन आयोजनों का असर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा देखने को नहीं मिला, क्योंकि पिछली सरकारों ने अपने कार्यकाल के अंतिम सालों में इस तरह का आयोजन करवाया था, जिसकी वजह से कार्यक्रमों में हुए समझौते क्रियान्वित नहीं हो सके। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने संयोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ, सरकार के कार्यकाल के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि कार्यक्रम में होने वाले प्रत्येक समझौते को धरातल पर उतारने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय हो। यही वजह रही कि अब तक करीब 9 लाख करोड़ के समझौते जमीन पर दिख रहे हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले में नए-नए औद्योगिक क्षेत्र सरकार की ओर से विकसित किए गए हैं, जहां पर देश और दुनिया के इन्वेस्टर को अपने उपक्रम खोलने के लिए जमीन आवंटित की जा रही है। सरकार की ओर से इन्वेस्टर्स को तमाम तरह की आधारभूत सुविधाएं- पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, मजदूर इत्यादि सभी तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की स्थापना हो। जिसकी वजह से एक तरफ जहां रोजगार के अवसर व्यापक स्तर पर पैदा हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को भी गति मिलने लगी है, और प्रदेश के विकास को भी तेज गति से रफ्तार मिली है। यह सारा काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह की आपस की बेहतर ट्यूनिंग और समन्वय से ही संभव हो पाया है।

पदम श्री, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जैसे कई बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार हासिल करके खुद का और राजस्थान का गौरव बढ़ाया



इंडियन मिलिट्री और विश्व खेल जगत में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के अभूतपूर्व उपलब्धियां और प्रदर्शन को देखते हुए, भारत सरकार ने भी इन्हें खूब सम्मान प्रदान किया है। जिसमें 2003 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 2004 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वर्ष 2005 में इन्हें पदम श्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें मिलिट्री में उल्लेखनीय प्रदर्शन पर अति विशिष्ट सेवा पुरस्कार भी प्रदान किया गया, यह पुरस्कार शांतिमय सैन्य पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। मिलिट्री में सर्विस के दौरान सिख रेजीमेंट की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें मिला है। राठौर ने अपने अब तक के जीवन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितने बड़े-बड़े पुरस्कार और ट्रफियां जीती है, जिन्हें सजाने के लिए एक बड़ा हॉल भी कम पड़ जाए। इसके अलावा वर्ष 2014 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद भी, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों की ओर से आए दिन इनका शानदार तरीके से वेलकम किया जाता रहा है। क्योंकि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जितने श्रेष्ठ और साहसी मिलिट्री के अधिकारी रहे, तो उतने ही दुनिया के सबसे निशानेबाज भी रहे। देश और दुनिया भर में कई बड़ी-बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल करके भारत का नाम रोशन किया। वर्ष 2004 से पहले भारत की आजादी के बाद



ओलंपिक में भारत को कभी भी पदक नहीं मिला था, लेकिन वर्ष 2004 में एथेंस में आयोजित ओलंपिक गेम्स में राठौर ने निशानेबाजी में रजत पदक हासिल करके ओलंपिक में एक नया इतिहास लिख दिया। हालांकि 2004 से पहले 2003 में मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में राठौर ने स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में 200 में 192 लक्ष्य का राष्ट्रमंडल में कीर्तिमान स्थापित किया, जो आज तक कायम है। इसके अलावा 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में राष्ट्रमंडल खेलों में कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया। 2006 में काहिरा में आयोजित निशानेबाजी प्रतियोगिता में भी राठौर ने स्वर्ण पद हासिल किया। इस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक के बाद एक कई बड़ी-बड़ी अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर निशानेबाजी में भारत को नई पहचान दी। राज्यवर्धन सिंह राठौर में इंडियन मिलिट्री अकादमी में शूटिंग के अलावा बास्केटबाल, वालीबाल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, वाटर पोलो में गोल्ड मेडल जीता, इसीलिए इन्हें ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेशनल डिफेंस एकेडमी की ओर से भी इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मध्य प्रदेश की रणजी क्रिकेट टीम में सिलेक्टेड भी हो चुके हैं राज्यवर्धन सिंह, वॉलीबॉल फुटबॉल के श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे



बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे हैं। पूर्व में इनका मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन दौरान ही नेशनल डिफेंस एकेडमी में इनका चयन होने के बाद, इनके माता जी ने इन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी को ही ज्वाइन करने की सलाह दी। इसके बाद राठौर ने नेशनल डिफेंस एकेडमी को ही अपने करियर का रास्ता चुना। हालांकि एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ-साथ, राठौर वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी जैसे खेलों में भी एक्जिस्ट खिलाड़ी के रूप में स्कूल के दिनों में माने जाते थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी इन्होंने इन सभी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन इन सब खेलों के बीच नेशनल डिफेंस अकादमी में पढ़ाई और प्रशिक्षण के दौरान इनकी निशानेबाजी की प्रतिभा और हुनर को देखकर मिलिट्री के बड़े अधिकारी भी काफी प्रभावित रहे। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी के प्रतियोगिताओं में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन से लंबे समय तक निशानेबाजी में पूरी दुनिया में अव्वल रहे, जो इंडियन मिलिट्री के साथ-साथ राजस्थान और हिंदुस्तान के लिए भी काफी गर्व की बात रही। इसलिए राज्यवर्धन सिंह राठौर शारीरिक और मानसिक रूप से बचपन से ही काफी मजबूत और स्मार्ट रहे। हालांकि इनके दादा, परदादा, पिता और ताऊ सभी इंडियन मिलिट्री में बड़े पदों पर रहे, इसलिए इन्हें बचपन से ही फैमिली में अनुशासित, संयमित, धैर्यवान और निष्ठवान रहने जैसे संस्कार मिले, जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी को हमेशा मजबूती

इनके पिता लक्ष्मण सिंह राठौड़ भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में रहे थे शामिल, दादा उदय सिंह मेजर और परदादा शार्दुल सिंह भी इंडियन मिलिट्री में बड़े पदों पर रहे

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का परिवार पिछले कई सालों से इंडियन मिलिट्री में अपनी सेवाएं दे रहा है। इनके पिता लक्ष्मण सिंह राठौड़ 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पैदल सैनिक के रूप में हिस्सा ले चुके हैं। इनके दादा उदय सिंह मेजर पद पर रहे, और उनके परदादा शार्दुल सिंह भी इंडियन मिलिट्री में बड़े पद पर रहे, और इनके ताऊ जगमाल सिंह ब्रिगेडियर पद पर रहे, और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की पत्नी भी इंडियन मिलिट्री में बड़े पद पर पोस्टेड रही। हालांकि राठौर की माता शिक्षिका थी, और इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, इसीलिए उनकी माता ने इन्हें क्रिकेट से दूर रहने की सलाह दी थी, जिसको उन्होंने स्वीकार भी किया, अन्यथा इनका मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन भी हो गया था। राठौर बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री धारी है, इसके अलावा पुणे स्थित नेशनल डिफेंस अकादमी में पढ़ाई के दौरान निशानेबाजी और कई अन्य खेलों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करके, राजस्थान के जैसलमेर जैसे रेतीले जिले में जन्म लेने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने निशानेबाजी की प्रतियोगिता में लंबे समय तक दुनिया के खेल जगत में अपने नाम का डंका बजाया। और अब भारतीय जनता पार्टी में इनकी गिनती श्रेष्ठ और कर्मठ नेताओं में होती है।

और अच्छी दिशा मिलती रही। जीवन में खेलों का कितना महत्व है, इसका आभास इन्हें बचपन से ही हो गया था। इसीलिए एक खेल नहीं, बल्कि कई खेलों में स्कूल के दिनों में इनकी श्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिनती होती थी। स्कूल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो टूर्नामेंट होते थे, उनमें एक नहीं बल्कि कई खेलों में इनका शानदार प्रदर्शन रहता था। और अब भी खेल और खिलाड़ियों के प्रति इनका नजरिया पहले की तरह ही है, हमेशा खेल और खिलाड़ियों की रक्षा और विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

भजनलाल सरकार के श्रेष्ठ मंत्रियों की सूची में शामिल हैं, मंत्री के रूप में इनके परफॉर्मेंस से भाजपा हाई कमान भी खुश



पूर्व में मोदी सरकार में राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से किए गए अच्छे कार्यों को देखते हुए ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन्हें कई बड़े डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी दी। राठौर के पास पांच बड़े मंत्रालय हैं, जिनमें उद्योग, सूचना और प्रौद्योगिकी, युवा और खेल मामले, कौशल और नियोजित डिपार्टमेंट तथा सैनिक कल्याण जैसे विभाग हैं। पिछले सवा दो साल में इन सभी डिपार्टमेंटों का बहुत ही प्रभावी तरीके से राठौर संचालन कर रहे हैं, जिसमें उद्योग मंत्री के रूप में राइजिंग राजस्थान के प्रत्येक समझौते को जमीन पर उतारने के लिए जिस गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं, उस से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा हाई कमान दोनों काफी प्रभावित और खुश हैं। क्योंकि पिछले 2 साल में प्रदेश में उद्योगों का एक शानदार माहौल बनने लगा है, जिसमें रोजगार के अच्छे अवसर भी पैदा हो रहे हैं, बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार मिल रहा है। इसलिए एक श्रेष्ठ उद्योग मंत्री के रूप में राठौर ने खुद को साबित करके दिखाया। इसी तरह से पिछले सवा दो साल में राजस्थान खेल जगत में भी हरियाणा और पंजाब की तरह विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने लगा है। राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा और विकास के लिए भी भजनलाल सरकार की ओर से पिछले सवा दो साल में कई बड़े कदम उठाए गए, कई तरह की बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गईं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरियां भी दी जा रही हैं। इसलिए पिछले 2 साल में राजस्थान में वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट और कई अन्य खेलों के स्तर में जबरदस्त सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकार उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा कर उनकी प्रतिभा को चमकाने में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। इस कार्य को खेल मंत्री के रूप में राठौर खुद देख रहे हैं, और हर खेल और खिलाड़ी को काफी गंभीरता से लेते हुए, प्रदेश में खेलों का एक अच्छा माहौल बनाने के साथ-साथ प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में प्रदेश की भजनलाल सरकार पिछले सवा दो साल में काफी हद तक कामयाब भी हुई है। इसलिए पिछले 2 साल में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर हरियाणा और पंजाब की तरह राजस्थान का दबदबा बनाने में कामयाब हुए हैं। यह सब कमाल हुआ है खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से किए गए प्रयासों की वजह से, क्योंकि केंद्र सरकार में भी खेल मंत्री के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेलों में छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा कर प्रतिभाओं को आगे लाया गया, और फिर उन्हें हर तरह से सुविधा उपलब्ध करवा कर एक श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में तैयार किया गया। इसके लिए प्रदेश में अब विभिन्न खेलों में अच्छे खेल मैदान, अच्छे प्रशिक्षक, खेलों के अच्छे साधन, यंत्र, उपकरण इत्यादि उपलब्ध करवाने के साथ-साथ खिलाड़ियों के खाने-पीने की भी अच्छी व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों दोनों के स्तर में जबरदस्त सुधार हुआ है। इसीलिए आज राजस्थान राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हरियाणा पंजाब की तरह विभिन्न खेलों में पदक हासिल करने लगा है। इसी तरह से प्रदेश में सैनिक कल्याण के लिए भी पिछले सवा दो साल में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। प्रदेश में रिटायर्ड सैनिकों के परिजनों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए प्रदेश में कई जगहों पर नए कार्यालय खोले गए हैं, ताकि रिटायर्ड सैनिकों को अपने कामकाज के लिए लंबा रास्ता तय करके जयपुर नहीं आना पड़े। इसके अलावा सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों के लिए भी राजस्थान सरकार हर तरह से अपने स्तर पर हर तरह से सुविधा उपलब्ध करवाती है। क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौर खुद श्रेष्ठ सैनिक रह चुके हैं, और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिक परिवारों की मनोदशा और स्थितियों को भी अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए प्रदेश में सैनिकों के कल्याण और विकास के लिए भी राठौर ने मंत्री के रूप में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, तकनीकी रूप से राजस्थान के युवाओं को पारंगत करने की दिशा में भी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के प्रयास और निर्णय काफी अच्छे रहे हैं। प्रदेश में युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए और युवाओं के करियर को गति देने के लिए, जहां युवा नीति बनाकर युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्र में पिछले सवा दो साल में प्रदेश में युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी मिली है, तथा भजनलाल सरकार की सुविधाओं और योजनाओं का फायदा उठाते हुए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी राजस्थान का युवा लगातार पारंगत होता जा रहा है। इसलिए पिछले 2 साल में राजस्थान का युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विभिन्न क्षेत्रों में खुद को साबित करता हुआ दिख रहा है, यह सब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की नीतियों और निर्णय का ही परिणाम है।

श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के एक और "लाल" का राजस्थान में कमाल



प्रदेश में अपने करीब 14 महीने के पुलिस महानिदेशक पद के कार्यकाल में राजीव कुमार शर्मा ने अपने बेस्ट सुपरविजन से प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की उससे आदिकाल में मथुरा में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण की ओर से राक्षसों के खिलाफ की गई विध्वंसकारी यादों को कट दिया है ताजा, पुलिस प्रबंधन और पुलिस आधुनिकरण में पश्चिमी जर्मनी हांगकांग जैसे देश में विशेष अध्ययन करने जाने वाले पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में स्मार्ट पुलिसिंग की ओर तेजी से बढ़ रही राजस्थान पुलिस, हर तरह के अपराध के आंकड़ों में 1 साल के भीतर ही आई है जबरदस्त गिरावट, विदेश में बैठे बड़े-बड़े गैंगस्टर से जुड़े बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर लाया जा रहा है राजस्थान

जयपुर। जैसे आदिकाल में मथुरा में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए धरती मां को राक्षसों से विहीन कर दिया था, ठीक वैसे ही आज कलयुग में मथुरा में जन्म लेने वाले एक और कर्मयोगी पुरुष के बेस्ट सुपरविजन में राजस्थान में अपराध जगत से जुड़े लोगों के विनाश का क्रम जारी है। जी हां, जब से प्रदेश में पुलिस महानिदेशक पद पर राजीव कुमार शर्मा की नियुक्ति हुई है, तब से लेकर अब तक राजस्थान पुलिस के कामकाज का बारीकी से विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से प्रदेश में पिछले 14 महीने में पुलिस की अपराधियों के खिलाफ की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई ने आदिकाल में भगवान श्री कृष्ण की ओर से राक्षसों के खिलाफ की गई विध्वंसकारी यादों को जीवंत कर रही है। इसे संयोग ही कहेंगे कि डीजीपी राजीव शर्मा का जन्म भी श्री कृष्ण की जन्म स्थल मथुरा में ही हुआ और श्री कृष्ण की तरह ही अपने प्रोफेशन में कर्मयोगी बनकर अपराध जगत से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके लोगों को राहत प्रदान कर रहे हैं, हालांकि राजस्थान पुलिस का पूरे देश की पुलिस में विशेष सम्मान और गौरव कई सालों से बना हुआ है और

पुलिस मुख्यालय में विराजमान वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के मार्गदर्शन, नवाचार, नए प्रयोग, सोच और कार्यशैली से राजस्थान पुलिस ने देश के अन्य राज्यों की पुलिस की तुलना में उत्कृष्ट कार्य किया है, लेकिन पिछले एक साल में राजस्थान में हर तरह के अपराध जगत से जुड़े लोगों के खिलाफ निरंतर एक विशेष अभियान चलाकर छोटे बड़े सभी अपराधियों की कमर तोड़ी है, वह लाजवाब है, जिससे बड़े से बड़े गैंगस्टर गैंग से जुड़े बदमाशों में भी खलबली मची हुई है। यही वजह रही की पिछले साल की तुलना में हर तरह के अपराध में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। दूध हत्या, लूट, डकैती, नकबजनी, दुष्कर्म, दुष्कर्म का प्रयास, पोक्सो एक्ट जैसे अपराधों के मामलों में जबरदस्त गिरावट आई है, तो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रदेश भर में की जा रही कार्रवाई से अपराधियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए हैं। इतना ही नहीं, अवैध रूप से कमाई गई संपत्तियों को भी नष्ट किया जा रहा है। विपक्ष चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आंकड़े आंकड़े होते हैं, आंकड़ों को गलत साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए पिछले 1 साल के आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस की कमान राजीव शर्मा के हाथ में दी थी, उस भरोसे और विश्वास पर मथुरा का यह 'लाल' पूरी तरह से खरे उतरे हैं।

प्रदेश में एनडीपीएस और साइबर क्राइम के मामलों में ऐतिहासिक कार्रवाई



वैसे तो प्रदेश में हर तरह के अपराधों में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा का साइबर क्राइम और एनडीपीएस एक्ट के मामलों पर गंभीरता से फोकस है। इसलिए राजीव शर्मा ने प्रदेश में नशे के अवैधकारोबार को जड़ से समाप्त करने के लिए पहले शानदार कार्य योजना तैयार की और कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए इन्होंने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करके जिन जिलों में नशे का कारोबार ज्यादा होता है, वहां पर स्थान चिन्हित करके अभियान चलाकर नशे के कारोबार में शामिल लोगों को अरेस्ट करने के अलावा एमडी फैक्टरीज और नशे के ठिकानों को समूल नष्ट करने के निर्देश दिए। यह अभियान पिछले कई महीनों से पूरे प्रदेश भर में संपादित किया जा रहा है और इस अभियान में रोजाना बड़े-बड़े नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों को अरेस्ट किया जा रहा है। दुर्गम स्थानों और जंगल में जाकर एमडी फैक्टरीज का पर्दाफाश करके मौके पर ही उसे समूल नष्ट किया जा रहा है और हाथों-हाथ फैक्ट्री का संचालन करने वाले लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस तरह से पूरे प्रदेश भर में गांजा, चरस, अफीम और एचडी बरामद करने की प्रक्रिया कई महीनों से लगातार जारी है। इस तरह की प्रक्रिया राजस्थान में पहले कभी देखने को नहीं मिली, जब निरंतर रूप से कई महीनों से नशे के कारोबार के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की

गई हो। हालांकि पहले भी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन इस तरह से निरंतर कई महीनों तक करवाई नहीं देखी गई। इसीलिए प्रदेश में नशे का कारोबार पंजाब की तरह तेजी से बढ़ रहा था, जो पंजाब की तरह राजस्थान के युवाओं और लोगों को भी नशे की पूरी प्रवृत्ति में फंसा रहा था। इस समस्या को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी गंभीरता से लिया और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा तो पहले से ही नशे के कारोबार के पूरी तरह से खिलाफ रही है। इसलिए पिछले 14 महीने के कार्यकाल में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जो कार्रवाई की है, उसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस कार्रवाई में सिर्फ नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा, बल्कि इस अवैध कमाई से अपराधियों ने जो संपत्तियां अर्जित की है, उन्हें बरामद और नष्ट भी किया जा रहा है। इस तरह से अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है तथा कई सालों से वांटेड चल रहे इनामी तस्करों को भी पकड़ने के लिए पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही है। इस मामले में प्रदेश से बाहर छिपे कई वांटेड प्रमुख तस्करों को पुलिस गिरफ्तार करके लाई भी है। इसलिए एनडीपीएस एक्ट के मामले में राजस्थान पुलिस के करवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इसी तरह से साइबर अपराध के मामलों पर अंकुश लगाने में भी राजस्थान पुलिस अग्रणी रही है। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के विशेष निर्देशन में सभी जिलों में पुलिस की ओर से साइबर अपराध के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक तरफ जन जागृति अभियान का आयोजन करके लोगों को इस बारे में कई तरह की जानकारीयां और टिप्स देकर साइबर फ्रॉड की चपेट में आने से बचाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी संख्या में फर्जी सिम मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्टेड करवा कर बंद करवाए हैं तथा इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को चिन्हित करने के लिए तकनीकी रूप से परफेक्ट पुलिस अधिकारियों की जिलेवार नियुक्ति की गई है, ताकि इस तरह के मामलों का पर्दाफाश करने में आसानी रहे। इस मामले में बड़ी संख्या में वे मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जो चोरी, लूट, और गुमशुदा थे, जिनका उपयोग साइबर अपराधी कर रहे थे। इस तरह से साइबर अपराधियों की भी कमर तोड़ने में राजस्थान पुलिस काफी कामयाब हुई है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में पुलिस ने बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट होल्ड करवाए हैं, ताकि लोग लूटने से बच सकें।

छोटे बड़े सभी गंभीर अपराधों में आई जबरदस्त गिरावट से खलबली



जानकारी के अनुसार राजीव कुमार शर्मा ने 3 जुलाई 2025 को राजस्थान पुलिस महानिदेशक पद पर कार्यभार ग्रहण किया और इसी दिन उन्होंने पुलिस मुख्यालय में विराजमान सभी बड़े आईपीएस अधिकारियों के साथ विशेष मीटिंग आयोजित की। हालांकि इस तरह की यह मीटिंग हर नया पुलिस महानिदेशक आयोजित करता है और यह मीटिंग ज्यादातर हाय हेलो और शुभकामनाएं बधाई देने तक ही सीमित रहती है, लेकिन राजीव शर्मा ने अपनी इस पहले ही मीटिंग में राजस्थान पुलिस के विजन, संकल्प और स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर सभी अधिकारियों को सामूहिक सहयोग और समन्वय के साथ काम करने को प्रेरित किया और जनता का पुलिस के प्रति भरोसा और विश्वास और मजबूत हो तथा प्रदेश में अपराध जगत से जुड़े लोगों का खात्मा किया जाए, इस विषय पर गंभीरता से काम करने के लिए सीनियर आईपीएस अधिकारियों को अपने जूनियर अधिकारियों को

ठीक तरह से टकल को ठीक तरह से हैंडल करने को कहा। इसके बाद राजीव शर्मा समय-समय पर नियमित रूप से रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षकों से मुलाकात करके जिलेवार अपराधों की समीक्षा करते रहे हैं और अपनी ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी समय-समय पर देखते रहे हैं। विशेष तरह के अपराधों के लिए विशेष तरह के अभियान की रणनीति तैयार करके कठोरता से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते रहे हैं। इसी का नतीजा रहा की पिछले साल की तुलना में अपराधों में 4.65 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष 2025 में पूरे प्रदेश में 99272 मामलेदार छुए थे, जबकि वर्तमान में 94652 मामले ही दर्ज हुए। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल की तुलना में हत्या के मामलों में 4.41 प्रतिशत, हत्या के प्रयास के मामलों में 11.17 प्रतिशत, डकैती के मामलों में प्रतिशत, लूट के मामलों में 19.93 प्रतिशत, अपहरण के मामलों में 4.72 प्रतिशत, दुष्कर्म के मामलों में 13.36 प्रतिशत, पोक्सो एक्ट के मामले में 20.90 प्रतिशत और एससी एसटी के मामलों में 18.81 प्रतिशत की गिरावट आई है तथा एनडीपीएस एक्ट के मामलों में पिछले साल की तुलना में 29.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्योंकि एनडीपीएस के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान पुलिस की ओर से पूरे प्रदेश भर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गांजा अफीम चरस का कारोबार करने वाले लोगों की धरपकड़ की जा रही है और एमडी फैक्ट्री काम मौके पर जाकर नष्ट किया जा रहा है तथा ऐसे मामलों में आरोपी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करके उन्हें जेल की सलाखों में भेजा जा रहा है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस बार राजस्थान पुलिस यूपी पुलिस की तर्ज पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है और अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को नष्ट और जप्त कर रही है। इसके अलावा पिछले 1 साल में राजस्थान पुलिस की लूट के मामले में रिकवरी की रेट 71 से बढ़कर 79.09 प्रतिशत, नकबजनी की रेट 9.58 से बढ़कर 58.24 प्रतिशत और चोरी की रिकवरी रेट 10.34 से बढ़कर 24.79 प्रतिशत बढ़ी है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की ओर से दुष्कर्म के मामलों में जांच की औसत अवधि 81 दिन से घटकर 52 दिन और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में जांच की औसत अवधि 78.2 से घटकर 51.2 प्रतिशत रह गई है। इस तरह से पिछले 14 महीने का राजस्थान पुलिस का कार्यकाल काफी शानदार और उत्कृष्ट रहा है।

प्रदेश में आईपीएस के रूप में 34 साल की बेदाग नौकरी



आईपीएस राजीव शर्मा की पहली पोस्टिंग 1992 में प्रदेश में हुई। 1992 से लेकर अब तक यानी 34 साल की आईपीएस की नौकरी में एक भी मौका ऐसा नहीं आया, जब किसी ने इन पर किसी भी तरह का कोई भी आरोप लगाए हो, ना तो पब्लिक की ओर से और ना ही राजनेताओं की ओर से कभी भी इनके कामकाज और निर्णय पर सवाल खड़े किए हो, जबकि राजीव शर्मा प्रदेश में दोसा, भरतपुर, झालावाड़, राजसमंद, जयपुर ट्रेफिक, जयपुर नॉर्थ इत्यादि जिलों में एसपी पद पर रहे। जयपुर में सीबीआई यूनिट में एसपी रहे, इसके अलावा भरतपुर और बीकानेर रेंज में पुलिस महानिदेशक पद पर भी रहे। इसके अलावा एसीबी में भी आईजी पद पर काम किया। जयपुर में जयपुर में पुलिस की विभिन्न शाखों में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद पर काम किया, तो पुलिस महानिदेशक के रूप में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग और लॉ एंड ऑर्डर विभाग में काम किया। इस बीच दिल्ली में भी सीबीआई में संयुक्त निदेशक और दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान और पुलिस विभाग की मुखिया के रूप में काम किया। इस दौरान बीच में छुट्टी लेकर विदेश में पुलिस प्रबंधन और पुलिस की व्यवस्था से जुड़े कई कोर्सों का अध्ययन करने के लिए जर्मनी और हांगकांग इत्यादि देशों में अध्ययन करने भी गए और विदेशों से काफी कुछ सीख कर आए, जो अब राजस्थान के पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनने में काफी सहायक साबित हो रहा है। राजीव शर्मा ने विभिन्न जिलों में पुलिस अधीक्षक पद पर रहते हुए अनेक ऐसे गंभीर अपराध की घटनाओं का पर्दाफाश किया, जो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुई थी। उन गंभीर घटनाओं को अगर यहां इस आलेख में लिखा जाए, तो एक आलेख नहीं कई आलेख लिखने पड़ जाए। पुलिस वालों में भी

वर्ष 2006 में पुलिस पदक और वर्ष 2014 में राष्ट्रपति पदक से हो चुके हैं सम्मानित

वैसे तो आईपीएस की नौकरी में राजीव शर्मा को अब तक बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं इत्यादि से पुरस्कार मिल चुके हैं, सम्मानित हो चुके हैं, कई तरह की ट्रॉफी मिल चुकी है, लेकिन वर्ष 2006 में पहले पुलिस पदक मिलना और फिर वर्ष 2014 में राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलना इनकी पर्सनालिटी के निखार में चार चांद लगा देता है। राजीव शर्मा में गजब की नेतृत्व क्षमता है और सामने बैठे पुलिस अधिकारी की बॉडी लैंग्वेज और हाव-भाव देखकर ही यह अंदाजा लगा लेते हैं कि यह अधिकारी इस कार्य में बिल्कुल फिट रहेगी। राजीव शर्मा की यह खूबी अब से नहीं, बल्कि जब जिलों के एसपी हुआ करते थे, तब भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कैसे और किस तरह से काम करवाया जा सकता है, इसकी कला इन्हें बखूबी से आती है। इसीलिए अपने विभाग के छोटे-बड़े सभी अधिकारियों पर कर्मचारियों में भी राजीव शर्मा खूब लोकप्रिय हैं। इसलिए प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, इन्हें ज्यादा से ज्यादा फोल्ड पोस्टिंग दी गई और ज्यादा से ज्यादा पुलिस में ऐसे विभागों के कामकाज की जिम्मेदारी दी गई, जो जनता की भलाई और अपराधियों से सीधे जुड़े हुए थे। सरकार ने इन्हें जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को बहुत ही शानदार और जानदार ढंग से इन्होंने निभाया भी और अपने कार्यों से सरकारों को ही नहीं, बल्कि जहां भी पोस्टेड रहे, वहां के लोगों को भी खूब राहत दी। इसीलिए सरकार के विजन और संकल्प को हमेशा साकार करते रहे और सरकार ने भी उनके कार्यों और उपलब्धियों का सम्मान करती रही और इन्हें अच्छी जगह पर पोस्टिंग देती रही।

अक्सर यह चर्चा सुनने को मिल जाती है कि गंभीर अपराध की घटनाओं का खुलासा करने में राजीव शर्मा का कोई मुकाबला नहीं। इसके अलावा पब्लिक और पुलिस के बीच बेहतर दोस्ताना संबंध बनाने के विषय पर भी राजीव शर्मा अब तक काम कर रहे हैं। जब एसपी हुआ करते थे, तब भी राजीव शर्मा की यही प्राथमिकता रहती थी कि पुलिस और पब्लिक के बीच परिवार और दोस्ताना जैसा संबंध हो, जिससे आधा क्राइम तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर दोस्ताना संबंध कायम करने के लिए आज भी डीजीपी के रूप में राजीव शर्मा सभी पुलिस अधिकारियों को इस विषय पर गंभीरता से काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। राजीव शर्मा के आकर्षक व्यक्तित्व, मिलनसार व्यवहार, उत्कृष्ट कार्यशैली, नई सोच और नए तरीकों के साथ बदमाशों से मुकाबला करने की प्रवृत्ति, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से काम करने की इनकी खूबी इन्हें एक अलग श्रेणी का आईपीएस अधिकारी बना देती है। इसीलिए मुख्यमंत्री शर्मा ने इन्हें इनके अनुभव और योग्यता को देखते हुए राजस्थान पुलिस की कमान हाथ में दी।

अपर्णा अरोड़ा के कुशल प्रबंधन और नवाचारों से खान विभाग में एक अच्छे अध्याय की शुरुआत



जयपुर। सीनियर आईएएस अपर्णा अरोड़ा अपने आईएएस पति अखिल अरोड़ा की तरह लो प्रोफाइल ऑफिसर के रूप में मानी जाती हैं। अरोड़ा को मीडिया की सुर्खियों में बने रहना भी पसंद नहीं है और अपना गुणगान करवाना भी पसंद नहीं करती, बल्कि चुपचाप अपने काम से मतलब रखती हैं। सरकार की ओर से जो जिम्मेदारी दी जाती हैं उसे बखूबी से, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से निभाती हैं, इसीलिए अब तक की करीब 33 साल की आईएएस की नौकरी में कभी भी वह पल नहीं आया जब इनके काम, व्यवहार और वर्किंग स्टाइल को लेकर किसी ने इनकी आलोचना की हो। इसीलिए प्रदेश में चाहे भाजपा की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस पार्टी की, हर सरकार की निगाह में यह महिला ऑफिसर एक कुशल और कर्मठ एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में रही। इसीलिए इन्हें प्रदेश में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें हर विभाग में हर जिम्मेदारी को अपर्णा अरोड़ा ने बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया। यही वजह है कि प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन्हें एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी दी है जो प्रदेश सरकार की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देने से तो सीधा जुड़ा हुआ है ही, इसके अलावा प्रदेश के विकास और पर्यावरण से भी जुड़ा है। जी हां, अपर्णा अरोड़ा के पास वर्तमान में खान और पेट्रोलियम विभाग की जिम्मेदारी है जो वर्तमान परिपेक्ष में काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि राजस्थान में अवैध

ईमानदार और कर्मठ आईएएस मानी जाने वाली इस महिला अधिकारी की वर्किंग स्टाइल और दबंगई से प्रदेश में अवैध खनन करने वालों के टूट रहे होसले, पिछले 4 महीने में करोड़-अरबों रुपए के अवैध खनन का हुआ पर्दाफाश। खान विभाग में अपने अब तक के करीब 4 महीने के छोटे से कार्यकाल में ही अपनी वर्किंग स्टाइल, नवाचारों और कड़े फैसलों से प्रदेश में अवैध खनन की गतिविधियों पर काफी हद तक लगा दिया है अंकुश, करोड़ अरबों रुपए के अवैध खनन का पर्दाफाश करवा कर प्रदेश सरकार की इनकम को बढ़ाने में भी निभा रही हैं अहम भूमिका, पड़ोसी राज्यों के खनन माफिया पर भी अंकुश लगाने में रही कामयाब।

खनन की समस्या कई सालों से लगातार चली आ रही है, जिसमें प्रदेश सरकार को तो हर साल खनन माफिया करोड़ अरबों रुपए का चुपचाप चूना लगाते रहे हैं, साथ ही पर्यावरण और वन संपदा की दृष्टि से भी प्रदेश को खनन माफिया नुकसान पहुंचाते रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करीब 4 महीने पहले काफी सोच विचार और भरोसा करके अपर्णा अरोड़ा को खान और पेट्रोलियम विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर पोस्टिंग दी थी। यह पोस्टिंग इस परिस्थिति में और भी महत्वपूर्ण बन जाती है जब खान मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के अधीन ही है। ऐसे में यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की निगाह में अपर्णा अरोड़ा काफी पहले से ही एक कुशल, कर्मठ और ईमानदार ऑफिसर के रूप में बनी हुई थी। और अब खान विभाग में इनकी प्रभावी मॉनिटरिंग और उनके शानदार प्रबंधन ने खान विभाग के कामकाज को जो गतिशीलता प्रदान की है वह काफी लाजवाब है, क्योंकि अगर पिछले 4 महीने में खान विभाग की गतिविधियों और कामकाज का आकलन करें तो निश्चित रूप से प्रदेश में अवैध खनन की गतिविधियों में काफी हद तक अंकुश लगा है। और पिछले चार महीने में प्रदेशभर में खान विभाग की ओर से अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई की गई और करोड़ों रुपए पेनल्टी के तौर पर वसूल किए गए, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी अब अपने उस निर्णय पर जरूर खुशी और संतुष्टि हो रही होगी जब उन्होंने अपर्णा अरोड़ा को खान विभाग की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया था।

इरादे नेक और बुलंद हो तो हर मुश्किल काम आसान बन जाता है

प्रदेश में अवैध खनन की समस्या अब से नहीं बल्कि कई सालों से निरंतर चली आ रही है। यह ऐसी समस्या है जिसको लेकर सरकारों को कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार सुनाई पड़ी है। सरकारों ने अपने-अपने स्तर पर कई तरह के कदम भी उठाए, कठोर निर्णय भी लिए, लेकिन यह भी सच है कि खनन माफिया धनबल और भुजबल के आधार पर तथा अपनी ऊंची राजनीतिक पहुंच की वजह से अपने गैर कानूनी धंधे को संचालित करते रहे। और राजस्थान जैसे स्टेट जिसमें करीब 85 तरह के विभिन्न खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ऐसे में देश भर के खनन माफिया की निगाह में राजस्थान शुरू से ही उनकी पसंद का स्टेट रहा है, इसीलिए यहां पर अवैध खनन की समस्या सरकार के लिए लाइलाज बीमारी की तरह बनी रही। लेकिन कहते हैं ना की अगर इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो तो फिर मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही करिश्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और निर्देशन में खान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने अपने अब तक के खान विभाग के छोटे से कार्यकाल में करके दिखाया है। अपर्णा अरोड़ा जो अपनी ईमानदारी और कर्मठता के लिए ब्यूरोक्रेसी में जानी जाती हैं, उनकी पर्सनैलिटी का असर उनके विभाग में पोस्टेड अधिकारियों और कर्मचारी पर भी देखने को मिला है। जिसमें खान विभाग की वर्किंग स्टाइल और खान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार पर सालों से कई तरह के सवाल खड़े होते थे, वे सवाल अब कोई खड़े नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में खान विभाग के कामकाज और कार्यशैली में एक नयापन और एक नई गतिशीलता आई है जिससे खान विभाग की पुरानी छवि तेजी से सुधर रही है। जिसमें ड्रोन सर्वे के माध्यम से जहां प्रदेश भर में वैध खनन में अवैध खनन का पता लगाकर भारी मात्रा में अलग-अलग तरह के खनिज संपदा की चोरी पकड़ी और फिर खनिज संपदा की चोरी करने वाले खनन माफिया से पेनल्टी के तौर पर करोड़ों रुपए वसूले गए, उससे कहीं ना कहीं प्रदेश में अवैध खनन की गतिविधियों में काफी हद तक अंकुश लगा है, क्योंकि ड्रोन सर्वे में दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ नजर आया। यह खान विभाग में एक अलग नवाचार था जिससे सालों से



वैध खान की आड़ में अवैध खनन का खुलासा हो रहा है, जिसको कोई जानकारी भी नहीं सकता क्योंकि यह एक ऐसी तकनीक है जो स्थिति को पूरी तरह से क्लियर करती है, जिसमें वैध और अवैध दोनों स्थितियां मौके पर पूरी तरह से क्लियर होती है, इसलिए यह ड्रोन सर्वे खान विभाग के लिए वरदान बन गया है। हालांकि इस ड्रोन सर्वे को लेकर खनन व्यवसाय से जुड़े लोग कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन खान विभाग ड्रोन सर्वे को अब किसी भी सूरत में बंद करने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग कई सालों से अवैध खनन का संचालन कर रहे थे, वे अब भारी भरकम पेनल्टी चुकाने के डर की वजह से चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर भी समेटने लगे हैं। यह जो नया बदलाव खान विभाग में देखने को मिला है इसका पूरा श्रेय अपर्णा अरोड़ा को दिया जा रहा है। क्योंकि सालों से खान विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर जाकर वैध और अवैध का पता लगाया करते थे, मौके की रिपोर्ट भी तैयार करते थे, लेकिन मिली भगत के खेल में सब कुछ गोलमाल हो जाता था और खनन माफिया आराम से अपने काम को अंजाम देते रहते थे। लेकिन अब यह बीते जमाने की बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देशन और मार्गदर्शन में खान विभाग का नेतृत्व कर रही अपर्णा अरोड़ा फुल फॉर्म में है। और अरोड़ा के मार्गदर्शन और प्रबंधन में प्रदेश भर में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जो नियमित रूप से प्रभावी कार्रवाई संपादित हो रही है, उसी का असर है कि एक तरफ जहां प्रदेश सरकार की तिजोरी में अवैध खनन करने वालों से पेनल्टी के रूप में भारी भरकम पैसा आ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदेश की प्रकृति और वन संपदा का नुकसान होना भी बच रहा है।

मेवाड़ की खनिज संपदा की सुरक्षा के लिए अपर्णा अरोड़ा का विशेष चक्रव्यूह



अपर्णा अरोड़ा के सुपरविजन में वैसे तो पूरे प्रदेश भर में अवैध खनन की रोकथाम के लिए ड्रोन सर्वे और कई अन्य तरीकों से मौके पर जाकर जांच पड़ताल करके अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पेनाल्टी वसूल की जा रही है, लेकिन प्रदेश के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा जैसे जिलों में विभिन्न तरह की खनिज संपदा के प्रचुर भंडार हैं। जिनके संरक्षण और

सुरक्षा के लिए तथा वैध और अवैध खनन का पता लगाने के लिए खान विभाग की ओर से प्रभावी सर्वे का कार्य लगातार चल रहा है। कई बार शिकायतों के आधार पर खान विभाग के अधिकारी खुद मौके पर जाकर और ड्रोन की सहायता से सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, तो कई बार खान विभाग की टीम अब अपने स्तर पर भी चुपचाप सर्वे के काम को अंजाम दे रही है, जिसका अवैध खनन करने वालों को पता ही नहीं चल पाता है। क्योंकि कई बार अवैध खनन करने वालों को जब यह जानकारी मिल जाती है कि खान विभाग की टीम यहां पर आ रही है, तो वे अपने ऊंचे राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके खुद को खान विभाग की कार्रवाई से बचाने में सफल हो जाते हैं। कई बार सेटिंग का खेल भी खेल लिया जाता है, लेकिन वर्तमान में खान विभाग का नेतृत्व कर रही अपर्णा अरोड़ा ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ निर्देशित किया हुआ है कि विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो लिफ्ट पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी तत्काल की जाएगी। इसके अलावा अरोड़ा खुद प्रदेश में जिलेवार रोजाना खान विभाग के कामकाज की समीक्षा करती है, रोजाना अधीनस्थ अधिकारियों से अपडेट लेती रहती हैं, और प्रदेश भर में संपादित की जा रही ड्रोन सर्वे रिपोर्ट और अधिकारियों और कर्मचारियों की मौके की रिपोर्ट, पेनल्टी शुल्क इत्यादि पर खुद नियमित रूप से निगरानी रखती हैं। इसलिए खान विभाग का स्टाफ भी अपने नेतृत्व को दबंग और ईमानदार देखकर खुद भी निष्ठा भाव के साथ काम करने के रास्ते पर चल पड़ा है। इसी का नतीजा है कि खान विभाग ने पिछले कुछ महीनों में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी काफी प्रभावित किया है। जानकारी के अनुसार अपर्णा अरोड़ा ने उदयपुर, बांसवाड़ा और आसपास के जिलों में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए बाकायदा आधा दर्जन से ज्यादा टीमों का गठन किया है, जिन्हें अलग-अलग इलाके की जिम्मेदारी दी गई है। इन टीमों की गतिविधियों और कार्रवाइयों पर अरोड़ा नियमित रूप से निगरानी रख रही हैं और नियमित रूप से इन टीमों के कामकाज की समीक्षा करती रहती हैं, अपडेट लेती रहती हैं और अपनी ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी देती रहती हैं। जिसका परिणाम यह है कि प्रदेश के मेवाड़ इलाके में काफी हद तक अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लग गया है और इन इलाकों में अवैध खनन करने वालों से भारी भरकम पेनल्टी शुल्क की राशि वसूल करके प्रदेश सरकार की तिजोरी में भी काफी पैसा जमा करवाया है।

गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्यों से अवैध खनन का परिवहन और आवागमन को रोकने के लिए कठोर प्रबंध किए



ऐसा नहीं है कि राजस्थान में मौजूद खनिज संपदा का ही अवैध तरीके से दोहन हो रहा हो, बल्कि राजस्थान के सीमावर्ती राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों से भी अवैध खनिज संपदा का आवागमन और परिवहन यहां हो रहा है। इसलिए पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध खनिज संपदा से भरे व्हीकल को पकड़ने के लिए खनिज विभाग की ओर से विशेष कदम उठाए गए हैं। इसमें पुलिस, जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया गया है। इसके अलावा खनिज विभाग की ओर से इस विशेष कार्य के लिए विशेष टीमों का भी गठन किया गया है, जो पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध खनिज संपदा से भरे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। इसमें अवैध बजरी का कारोबार भी जबरदस्त तरीके से संचालित हो रहा था, यह कारोबार पिछले कई सालों से पुलिस और प्रशासन तथा खनिज विभाग की आंख में धूल झोंक कर किया जा रहा था। इस अवैध बजरी खनन के कारोबार से राजस्थान के उपभोक्ता भी काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें महंगी दर पर मजबूरी में बजरी खरीदनी पड़ रही थी। इसके अलावा

प्रदेश के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर जैसे जिलों में अनेकों तरीके के खनिज संपदा हैं, जिनका नियम और कानून के खिलाफ चोरी छुपे माफिया दोहन कर रहे थे और सरकार को हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा रहे थे। और राजस्थान की खनिज संपदा का गलत तरीके से दोहन करके उन्हें पड़ोसी राज्यों के खनन माफिया को सप्लाई किया जा रहा था, जो राजस्थान की इकोनॉमी के लिए तो नुकसानदायक था ही, इसके अलावा प्रदेश की प्रकृति और वन संपदा की सुरक्षा के लिए भी खतरा बना हुआ था। इसलिए पड़ोसी राज्यों के खनन माफिया का राजस्थान के खनन माफिया कि इस बेजोड़ दोस्ती और संपर्क को तोड़ने के लिए खान विभाग की ओर से कुछ विशेष नवाचार और विशेष प्रबंध किए गए। जिसकी वजह से अब काफी हद तक गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से, पहले जहां रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में भी कई बार मिली भगत के माध्यम से बड़ी संख्या में अवैध खनिज संपदा से भारी वाहनों का प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आना-जाना लगा रहता था, उस पर अपर्णा अरोड़ा ने प्रभावी करवाई करके काफी हद तक पड़ोसी राज्यों के खनन माफिया के गठजोड़ को तोड़कर रख दिया है। इसके लिए सीमावर्ती जिलों के प्रशासन और पुलिस के अलावा वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ अपर्णा अरोड़ा नियमित रूप से अपना संवाद जारी रखती हैं, क्योंकि अरोड़ा यह अच्छी तरह से जानती हैं कि अकेला खनिज विभाग खनन माफिया की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग सकता, इसलिए प्रशासन और पुलिस को साथ अरोड़ा निरंतर संपर्क में रहती हैं।



आईएस की 33 साल की बेदाग सर्विस, बड़े-बड़े महत्वपूर्ण विभागों का प्रभावी तरीके से किया संचालन



वर्ष 1993 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी अपर्णा अरोड़ा कि अब तक की 33 साल की सरकारी सर्विस का रिकॉर्ड बेदाग और काफी महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि एसडीओ, अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त जैसे पदों पर काम करने के साथ साथ ग्रामीण विकास और पंचायती राज, स्कूली शिक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, अल्पसंख्यक मामला, ट्राईबल, फाइनेंस, टैक्स, माइंस एंड मिनरल्स, पेट्रोलियम जैसे अनेकों बड़े महत्वपूर्ण विभागों में बड़े पदों पर रहने के दौरान हर विभाग में उत्कृष्ट कार्य करके सरकारों को भी प्रभावित किया और प्रदेश की जनता के हितों की भी रक्षा की। तथा प्रदेश के विकास को गति देने में पूरी निष्ठा के साथ काम किया और जरूरत पड़ने पर बजट तैयार करवाने में भी सरकारों को अच्छी सलाह और सुझाव दिए, क्योंकि अपने पति अखिल अरोड़ा की तरह वित्त प्रबंधन के मामले में भी काफी कुशल हैं। बड़ी बात यह है कि इतनी लंबी सरकारी सर्विस में बड़े-बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में रहने के दौरान एक बार भी ऐसा कोई अवसर नहीं आया जब अपर्णा अरोड़ा को लेकर किसी ने भी किसी भी तरह का कोई मामूली एलिगेशन लगाया हो या फिर किसी ने भी उनके कामकाज और इनके व्यवहार पर आपत्ती जताई हो। महिला होने के बावजूद भी नेतृत्व क्षमता के मामले में अरोड़ा का कोई जवाब नहीं, और जितनी सरल और सहज दिखती हैं उतनी ही नियम और कानून की पालना करवाने में काफी कड़क भी मानी जाती है। इनकी नेतृत्व क्षमता और दबंग छवि का ही

परिणाम है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन्हें खान विभाग जैसे चुनौती पूर्ण डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी।

अखिल अरोड़ा और अपर्णा अरोड़ा की कपल जोड़ी राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की आईएस लॉबी में हमेशा काफी पॉपुलर और चर्चित रही है



जानकार लोगों का कहना है कि अपर्णा अरोड़ा और इनके पति अखिल अरोड़ा दोनों ही वर्ष 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। दोनों का स्वभाव और काम करने का तरीका बिल्कुल एक समान है। दोनों ही काफी सरल, सहज, सौम्य, ईमानदार और कर्मठ अधिकारी माने जाते हैं और दोनों चुपचाप काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। और दोनों ही बोलते कम हैं और काम ज्यादा करते हैं। और यह दोनों ही अधिकारी राजस्थान में सभी पार्टियों की सरकारों के काफी भरोसेमंद अधिकारी रहे हैं, और इन दोनों ही अधिकारियों को प्रदेश में सभी पार्टियों के सरकारों ने महत्वपूर्ण विभागों में महत्वपूर्ण जगहों पर पोस्टिंग दी है। और इन दोनों ही अधिकारियों ने सरकार से मिली जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हुए प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए प्रदेश के विकास को गति देने में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसीलिए आज भी यह दोनों ही अधिकारी भजनलाल सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टेड हैं। इसीलिए इस आईएस दंपति को राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में ही नहीं, बल्कि देश की आईएस लॉबी में काफी सम्मान और इज्जत मिली हुई है। अपर्णा अरोड़ा के पति अखिल अरोड़ा वर्तमान में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर नियुक्त हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक अच्छे सारथी के रूप में नजर आ रहे हैं।

खान विभाग की छवि को सुधारने में पूरे मन से जुटी हैं अपर्णा अरोड़ा

सालों से राजस्थान का खान विभाग भ्रष्टाचार को लेकर पूरे देश में चर्चा में रहा है। खान विभाग के पुराने इतिहास को देखें तो करोड़ों के घोटाले यहां उजागर हुए हैं, जिसमें कई बड़े-बड़े अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे भी गए हैं, जिसमें पूर्व आईएसएस अशोक सिंघवी जैसे अधिकारी भी जेल गए जिन पर 20 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके अलावा सालों से समय-समय पर एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से भी खान विभाग में कार्रवाई की जाती रही है। इसलिए यह विभाग प्रदेश में सरकारों के लिए हमेशा ही बड़ा चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि इनकम की दृष्टि से खान विभाग राजस्थान सरकार के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यहां पर 85 तरह के अलग-अलग किस्म की खनिज संपदा अलग-अलग जिलों में प्रचुर मात्रा में है। इसके अलावा बजरी खनन भी यहां पर व्यापक पैमाने पर होता है, इसलिए बजरी माफिया और खनन माफिया से खान विभाग के स्टाफ की दोस्ती हमेशा चर्चा में रही है। लेकिन पिछले सवा दो साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और निर्देशन में खान विभाग के कामकाज और कार्यशैली में एक नयापन और गतिशीलता आई है, जिसमें कहीं ना कहीं खान विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों में भी तेजी से गिरावट आ रही है। और अपर्णा अरोड़ा के हाथों में खान डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हाथ में आने के बाद पिछले करीब 4 महीना में खान विभाग एक अलग ही कलेवर और अंदाज

में नजर आने लगा है। जिसमें प्रदेश भर में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ हो रही प्रभावी कार्रवाइयों ने प्रदेश भर में अवैध खनन करने वाले लोगों के हौसले काफी कमजोर कर दिए हैं, और कई लोगों ने तो खान विभाग की प्रभावी कार्रवाई को देखकर अपने बोरिया बिस्तर भी समेट लिए हैं, क्योंकि खान विभाग की ओर से भारी भरकम पेनल्टी की राशि वसूल की जा रही है। लंबे समय से वैध खानों में चोरी छुपे अवैध खनन का जिस तरह से प्रदेश भर में कई जगहों पर खान विभाग की ओर से पर्दाफाश किया गया, उसके बाद प्रदेश भर में सालों से अवैध खनन को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे लोगों के हौसले टूट गए हैं। क्योंकि अरोड़ा खुद नेक और ईमानदार अधिकारी रही हैं, इसलिए उनकी ईमानदारी और उनकी दबंगई और उनके कड़े मिजाज का असर खान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीधा पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं खान विभाग की कार्य शैली और कामकाज को पारदर्शक बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसलिए अगर खान विभाग के पिछले चार महीना के कामकाज और गतिविधियों को देखें तो यह जानकर काफी तसल्ली होती है कि खान विभाग जो सालों से अपने कामकाज और कार्यशैली को लेकर बदनाम होता रहता था, आज उस तरह के हालात कम से कम खान विभाग में नजर नहीं आ रहे, जिसका पूरा श्रेय खान विभाग की टॉप ऑफिसर अपर्णा अरोड़ा को दिया जा रहा है।

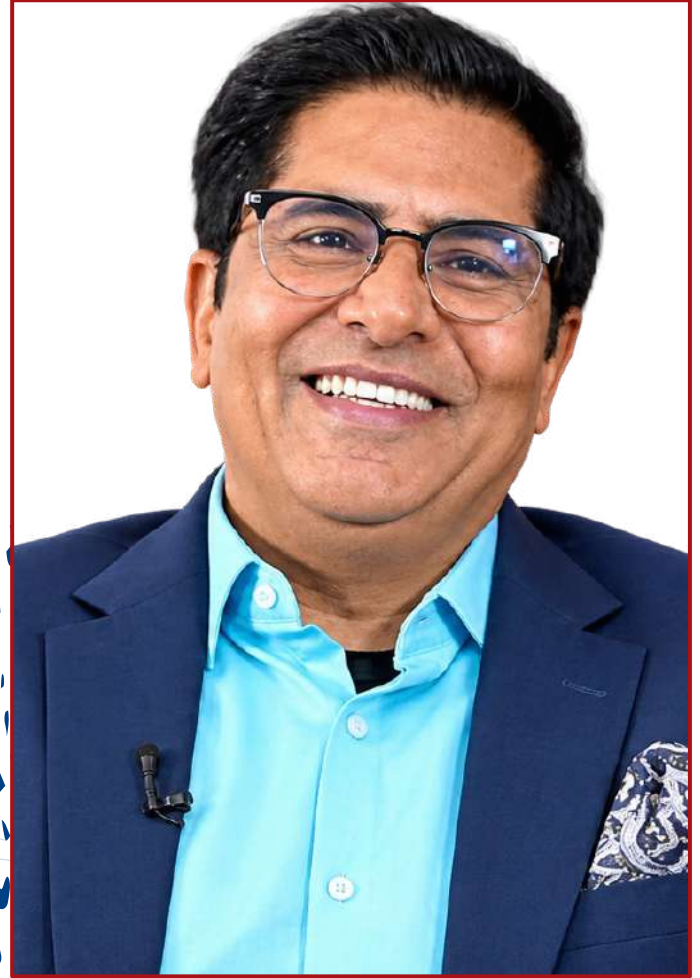
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में खान विभाग अग्रिम पंक्ति में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिन-रात एक किए हुए हैं। और प्रदेश के सभी सरकारी डिपार्टमेंटों के कामकाज को गतिशील बनाने और प्रदेश में भविष्य को ध्यान में रखते किया विकास कार्यों की कड़ी को आगे बढ़ाने में भजनलाल सरकार तेजी से काम कर रही है, जिसमें अपर्णा अरोड़ा के नेतृत्व में प्रदेश का खान विभाग भी अब प्रदेश सरकार की तिजोरी को भरने में सतत रूप से प्रयास कर रहा है। क्योंकि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, इसलिए इनका अगर ठीक तरीके से दोहन हो और खनिज संपदा का गलत तरीके से उपयोग नहीं हो, खनिज संपदा का अवैध खनन नहीं, तो राजस्थान का

अकेला खनिज डिपार्टमेंट ही सरकार की तिजोरी को भरने की पूरी क्षमता रखता है। इस बात को खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जानते हैं, इसीलिए एक तरफ जहां अवैध खनन करने वालों को चिन्हित करके उनसे भारी भरकम पैसा पेनल्टी के रूप में वसूल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अपशिष्ट खनिज संपदा में मूल्यवान संसाधन एकत्रित करने के क्रम में भी खान विभाग तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए सरकारी स्तर पर धनबाद की एक संस्था से समझौता भी हो चुका है, जिसमें अपशिष्ट खनिज पदार्थ में कई तरह के मूल्यवान संसाधन मिलने के संकेत मिले हैं, जो एनर्जी के क्षेत्र में काफी उपयोगी बताए गए हैं। इसलिए खान विभाग हर तरह से सरकार की तिजोरी को भरने का प्रयास कर रहा है, जिसमें पिछले करीब 4 महीना में खान विभाग की रिकॉर्ड तोड़ इनकम हुई है, जो कहीं ना कहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार के विकास कार्यों को गति देने में सहायक साबित होगी, जिससे निश्चित रूप से विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने में अच्छी मदद मिलेगी। इसलिए कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में खान विभाग का जो कामकाज रहा है और खनन माफिया से जिस तरह से पेनल्टी के रूप में पैसा वसूल किया जा रहा है, और नियम और कानून के आधार पर कोर्ट के आदेशों की पालन करते हुए प्रदेश का खान विभाग नई खानों का पारदर्शक तरीके से आवंटन करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में खान विभाग राजस्थान की तिजोरी में पैसा लाने में सबसे आगे नजर आएगा, जिसका श्रेय भी अपर्णा अरोड़ा को दिया जा सकता है।

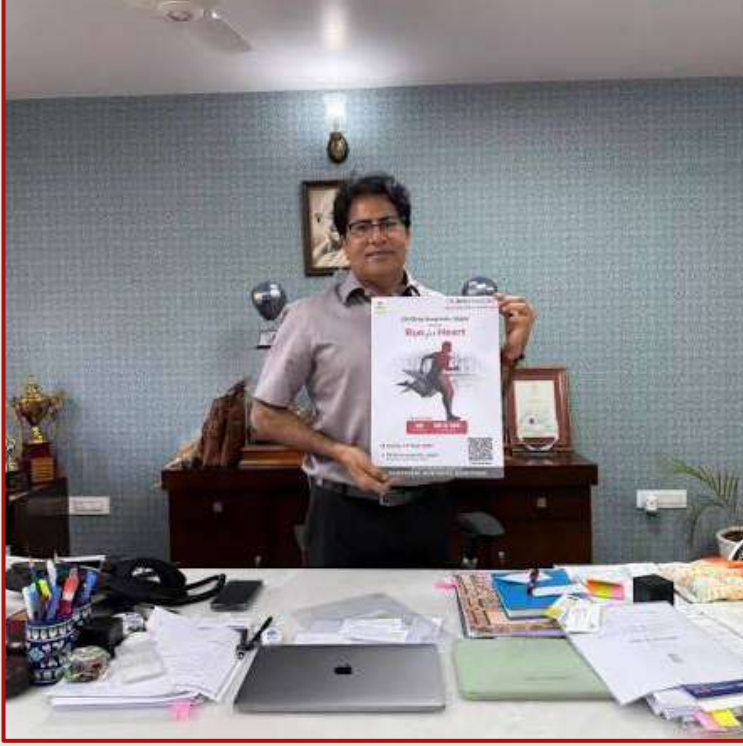
गांव से जुड़ी समस्याओं और विकास को बेहतर तरीके से समझने वाले आईएएस "राजेश यादव"

प्रदेश में अजमेर, दोसा, पाली, सवाई माधोपुर, कटौली, मिरोही, जैसलमेर जिलों में कलेक्टर पद पर रहने के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की संभावना को तलाश कर ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले 1996 बैच के इस अधिकारी ने राजस्थान में करीब करीब सभी महत्वपूर्ण विभागों में शानदार परफॉर्मेंस करके हर पार्टी की सरकार का जीता दिल और विश्वास।



जयपुर। प्रदेश में मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करवाने के मामले में देश भर में सुर्खियों में रहने वाले, 1996 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश यादव, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को तलाशने के मामले में विशेषज्ञ और माहिर ऑफिसर माने जाते हैं। प्रदेश में अब तक की अपनी आईएएस की नौकरी में आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में कलेक्टर पद और प्रदेश के पंचायत राज विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी पद पर रहने के दौरान, यादव ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण इलाकों में अपनी वर्किंग स्टाइल, नवाचार और समर्पित भाव से केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से संचालित की जा रही विभिन्न तरह की जनकल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से संपादित ही नहीं करवाया, बल्कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को बहुत ही सफलतापूर्वक क्रियान्वित करवा कर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के कल्याण और विकास के रास्ते को काफी सरल और सुगम भी बनाया।

इसीलिए इन्हें मनरेगा जैसी योजना के कुशल संचालन के लिए पुरस्कृत भी किया गया। लेकिन, इस पुरस्कार से भी ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से ताल्लुक रखने वाले यह ऑफिसर, राजस्थान जैसे विशाल मरू प्रदेश कि ग्रामीण क्षेत्र की लाइफ स्टाइल, समस्याओं और ग्रामीण क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में भी बहुत अच्छी समझ और पकड़ रखते हैं। शायद यही वजह रही कि इन्होंने प्रदेश में जहां भी और जिस भी जिले में सरकार ने काम करने का मौका दिया, वहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी इनके अच्छे कार्यों और नवाचारों को खूब याद करते हैं। राजेश यादव खुद भी कहते हैं कि गांव से जुड़ा कोई अधिकारी या फिर अपना बचपन और स्कूली शिक्षा गांव में ही बिताने वाला अधिकारी, गांव की समस्याओं और गांव के विकास से जुड़े मुद्दों और विषयों को ज्यादा अच्छी तरह से समझता है। हालांकि यादव यह भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र के रहने वाले अधिकारी गांव को नहीं समझते, लेकिन गांव से जुड़ा अधिकारी ज्यादा बेहतर तरीके से और आसानी से ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं और विकास को समझता है।



प्रदेश में शानदार और जानदार रहा अब तक की सर्विस का रिकॉर्ड

राजेश यादव वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा पद पर पोस्टेड हैं। इससे पहले राजेश यादव प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में कलेक्टर पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा जयपुर नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी, आरसीडीएफ के प्रबंधक और प्रदेश में स्टेट रोड कारपोरेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग में भी महत्वपूर्ण पद पर पोस्टेड रहे हैं। इसके अलावा पंचायत राज विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, श्रम विभाग, स्कूल, बॉयलर जैसे महत्वपूर्ण विभागों में बड़े पदों पर रहने के

यादव यह भी कहते हैं कि भारत जैसे ग्रामीण प्रधान देश की तरक्की और विकास गांव पर ही ज्यादा निर्भर है, क्योंकि आज भी करीब 75 प्रतिशत से ज्यादा आबादी हिंदुस्तान के गांव में ही रहती है। इसलिए शहर का विकास अपनी जगह पर है, लेकिन गांव का विकास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। गांव के समुचित विकास बिना और ग्रामीण क्षेत्र की खुशहाली के बिना, भारत जैसे ग्रामीण प्रधान देश के विकसित राष्ट्र बनने की कल्पना बेमानी होगी। यादव यह भी कहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भजनलाल सरकार, दोनों सरकारों का पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कल्याण और विकास पर ज्यादा है। इसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र शहर की तरह रोशन हो रहे हैं। युवा, महिला, मजदूर और किसान की लाइफ स्टाइल और सोच तेजी से बदल रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के इनकम के स्रोत बढ़ रहे हैं। आज सभी तरह के हाई प्रोफाइल एग्जाम में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में बड़े-बड़े ग्रुप के विश्वविद्यालय, कॉलेज, चिकित्सालय इत्यादि की तेजी से स्थापना हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की ओर से औद्योगिक क्षेत्र डेवलप की जा रहे हैं। इन सब बदलाव से राजस्थान में भी ग्रामीण क्षेत्र में लगातार क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश के कई जिलों में और भी ज्यादा गंभीरता से काम करने की लगातार सतत जरूरत है, जिसमें सरकार और ब्यूरोक्रेट दोनों अपना काम कर रहे हैं।

दौरान, अपनी वर्किंग स्टाइल, नवाचार, अपने अच्छे व्यवहार और समर्पित भाव से उत्कृष्ट काम करके प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की सरकारों को काफी प्रभावित किया। इसीलिए अब तक की सर्विस में चाहिए प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, हर पार्टी की सरकार ने राजेश यादव की ईमानदारी और इनके काम करने के प्रभावी तरीकों और नवाचारों से प्रभावित होकर इन्हें महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई। जिसमें इन्होंने हर जिम्मेदारी को बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से निभाया। जिसमें दोसा, अजमेर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में कलेक्टर पद पर रहने के दौरान, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के कल्याण और विकास के लिए बहुत ही शानदार तरीके से जनकल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से संपादित करवाया। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में भी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से संपादित करवाए गए विकास कार्यों और परियोजनाओं का बहुत ही पारदर्शक तरीके से क्रियान्वित करवाया। कलेक्टर के रूप में इनके कामों और उनके अच्छे व्यवहार को आज भी जिलों के लोग याद करते हैं और इन्हें काफी मिस करते हैं। मनरेगा में इनकी ओर से की गई व्यवस्थाओं और नवाचारों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा हुआ, और मनरेगा में भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी प्रयास किया, जिसके अच्छे नतीजे भी मिले। नौकरी के शुरुआत में जोधपुर और जैसलमेर में अतिरिक्त कलेक्टर पद पर रहने के दौरान भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से इनके जुड़ाव की जो शुरुआत हुई, वह आज तक कायम है।

मुस्कुराते हुए राजेश यादव ने कहा-इंडियन पापा को खुश और संतुष्ट करना काफी मुश्किल

एक मुलाकात के दौरान राजेश यादव ने कहा कि उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा के पहले ही चांस में सफलता हासिल की। इसके लिए कानपुर यूनिवर्सिटी में बीटेक इलेक्ट्रिकल की डिग्री लेने के बाद अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए वे अपने घर से अकेले ही दिल्ली आए। जहां करीब 1 साल तक रहकर उन्होंने परीक्षा की तैयारी की, जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स और हिंदी लिटरेचर दोनों विषय शामिल थे। जिसमें मैथ्स उनकी शुरु से ही बहुत अच्छी रही है और आज भी अच्छी है। लेकिन उनके पास बीटेक इलेक्ट्रिकल की डिग्री थी, लेकिन मैथ्स के साथ एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना जरूरी था। जिसमें हिंदी लिटरेचर में उनकी जिज्ञासा और रुचि बहुत पहले से ही थी, इसीलिए उन्होंने हिंदी लिटरेचर को एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया। लेकिन हिंदी लिटरेचर का चयन करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती और मुश्किल भरा निर्णय था, क्योंकि बीटेक इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई का हिंदी लिटरेचर से सीधा जुड़ाव नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी रुचि और जिज्ञासा को ही अपना जुनून बनाया, और हिंदी लिटरेचर की विशेष रूप से तैयारी शुरू की। जिसमें दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान में भी सिर्फ 15 दिन तक ही हिंदी लिटरेचर की तैयारी की, लेकिन संस्थान से हिंदी लिटरेचर की परीक्षा की तैयारी में उन्हें जो कुछ चाहिए था, वैसा उन्हें मिल नहीं रहा था। कहीं ना कहीं विषय सामग्री और शिक्षकों से ठीक तरह से संतुष्ट नहीं मिल रही थी, इसलिए संस्थान में सिर्फ 15 दिन तक ही पढ़ाई करने के बाद संस्थान को छोड़ दिया। हिंदी लिटरेचर में अपनी कमजोरी को ही अपना हथियार समझा, और स्वयं की प्रेरणा और कड़ी मेहनत से उन्होंने हिंदी लिटरेचर से जुड़ी सभी तरह की परीक्षा की विशेष सामग्री का संकलन करके उनके नोटिस बनाए। फिर रात में करीब 2:00 बजे शांत वातावरण में विशेष सामग्री को अपनी जुबान से ही ऑडियो रिकॉर्ड किया, और फिर मॉर्निंग वॉक, भ्रमण और फील्ड में रहने के दौरान भी हिंदी लिटरेचर के इन ऑडियो को सुनकर अपनी तैयारी करते रहे। इस दौरान दिल्ली में जिस इलाके में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, वहां



देश के कोने-कोने से आए अन्य स्टूडेंट भी बड़ी संख्या में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इसलिए अन्य स्टूडेंटों से भी उनकी पढ़ाई को लेकर डिसकस होता रहता था। उनमें कई स्टूडेंटों का आईएएस में सिलेक्शन भी हो गया, जिनमें कई उनके गहरे दोस्त थे और आज भी हैं। इस तरह से करीब 1 साल तक दिल्ली में परीक्षा की तैयारी करने के बाद वापस उत्तर प्रदेश अपने घर आ गए। फिर अपने ख्वाब और संकल्प को पूरा करने के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी। जब उनका इस परीक्षा में सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने अपने पिता को जब यह खुशखबरी सुनाई तो उनके पिता ने कहा कि रैंक थोड़ी अच्छी मिल जाती तो तुमको होम केडर मिल जाता। राजेश यादव ने साक्षात्कार में मुस्कुराते हुए कहा कि कहीं ना कहीं उनके पिता उनकी इस बड़ी उपलब्धि से खुश तो हो रहे थे, लेकिन ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनके दिल में यह था कि रैंक और अच्छी मिल जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अपने पिता पर बहुत गर्व है, वैसे भी इंडियन पापा को पूरी तरह से संतुष्ट और खुश करना काफी मुश्किल है। इसलिए मैंने अपने पापा से कहा पापा, मेरी उपलब्धि पर थोड़ा तो मुस्कुरा दीजिए। इसके बाद उनके पापा ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद भी दिया, और उन्होंने कहा कि हमेशा सर्विस में ईमानदारी से गरीब निर्धन लोगों के कल्याण के लिए सतत रूप से काम करते रहना है।

शिक्षा विभाग में भजनलाल सरकार के विजन और संकल्प को साकार करने में निभा रहे शानदार भूमिका



प्रदेश में पिछले 6 महीने में शिक्षा विभाग के कामकाज और आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने में राजेश यादव की भूमिका की काफी प्रशंसा हो रही है। क्योंकि प्रदेश में स्कूलों के आधारभूत ढांचे और स्कूलों में शैक्षणिक और अन्य आधारभूत व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता शुरू से ही कई तरह के आरोप लग रहे थे, और राजस्थान विधानसभा के अंदर और राजस्थान विधानसभा के बाहर दोनों ही जगह पर कांग्रेस पार्टी के नेता मीडिया में बयान बाजी करके शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर गहरी नाराजगी प्रकट कर रहे थे। झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से प्रदेश की भजनलाल सरकार पर हमलावर हो गए थे। इसीलिए शिक्षा विभाग के आधारभूत ढांचे के विकास और बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई बड़े निर्णय भी लिए, और स्कूलों की आधारभूत व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए और जर्जर स्कूलों को सुधार के लिए भारी मात्रा में सरकार की ओर से बजट भी जारी किया गया। लेकिन सरकार की ओर से स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जारी किए गए एक-एक पैसे का सदुपयोग हो, और जो पैसा शिक्षा विभाग के लिए मंजूर किया गया है वह पैसा शिक्षा विभाग सुधार के लिए ही खर्च हो, इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजेश यादव के अनुभव और उनकी प्रशासनिक कुशलता तथा ईमानदारी को देखकर करीब 6 महीने पहले यादव को शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया, जिसके अब अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में पिछले 6 महीने में हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है, जिसमें स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। जिसमें शिक्षकों, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों के लिए भी गाइडलाइन निर्धारित की गई है, तो दूसरी तरफ ग्राम

पंचायत और संबंधित जनप्रतिनिधियों से भी लगातार संवाद और संपर्क करके स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने के सतत प्रयास जारी हैं। जानकारी के अनुसार राजेश यादव जिलेवार जिले की शैक्षणिक व्यवस्थाओं और स्कूलों के आधारभूत ढांचे और आधारभूत व्यवस्थाओं के बारे में नियमित रूप से फीडबैक लेते रहते हैं। जहां-जहां पर स्कूलों में विकास कार्य और निर्माण कार्य संचालित हो रहे हैं, उन पर खुद कड़ी निगरानी रख रहे हैं, और संबंधित अधिकारियों से नियमित रूप से फीडबैक लेते रहते हैं। कई बार राजेश यादव खुद स्कूलों का जाकर मौके पर निरीक्षण करते हैं, और किसी भी स्कूल के बारे में किसी भी तरह की कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुधार और छात्र-छात्राओं में नैतिक आचरण को लेकर भी शिक्षा विभाग में नवाचार जारी हैं। शैक्षणिक और खेल गतिविधियों के साथ स्कूलों में वाद विवाद, निबंध लेखन प्रतियोगिता, योग, व्यायाम जैसे विषय पर भी राजेश यादव का विशेष फोकस रहता है। स्कूलों में छात्र-छात्राओं को हर तरह से परफेक्ट बनाया जाए और उनके शारीरिक और मानसिक विकास को लगातार गति देकर उनकी शानदार पर्सनालिटी बनाई जाए, इन सब विषयों को लेकर शासन सचिवालय स्तर पर लगातार जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करके स्कूल प्रशासन की ओर से शासन सचिवालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसका भी पता लगाया जाता है, और जो भी शासन सचिवालय के आदेश और निर्देश की अवहेलना करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई दी जाती है। इस तरह से शिक्षा विभाग में राजेश यादव की नियुक्ति के बाद एक अच्छा और प्रभावशाली वातावरण देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं राजेश यादव की श्रेष्ठ नेतृत्व क्षमता को उजागर कर रहा है।

ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत और संकल्पित रहे यादव



जानकारी के अनुसार राजेश यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ, इसलिए उनकी स्कूली शिक्षा फोर्थ स्टैंडर्ड तक स्थानीय स्तर गांव में ही हुई। क्योंकि इनके पिता कृषि विभाग में अधिकारी थे, इसलिए उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगह पर उनकी नियुक्ति होती रही। इसलिए इनकी फोर्थ क्लास के बाद की स्कूल की पढ़ाई अलग-अलग जगह पर संपादित हुई। लेकिन बचपन से ही इनके परिवार वालों का ग्रामीण टच रहा, भले ही इनके पिता की नौकरी शहरों में रही हो, लेकिन ग्रामीण परिवेश से लगातार जुड़े रहे, जिसका बचपन से ही सीधा असर राजेश यादव की पर्सनालिटी पर भी पड़ा। यादव बचपन से ही ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को समझने लगे थे। अपनी आंखों से



गरीब मजदूर की पीड़ा को सहते भी देखा, किसान और खेती के व्यवसाय में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की कठिन जिंदगी को भी अपनी आंखों से देखा। इन सारे अनुभवों का समावेश यादव की जिंदगी में बचपन से ही हो गया था। इसलिए गांव और शहरी लाइफस्टाइल और समस्याओं के भेद को यादव आईएएस बनने से पहले ही अच्छी तरह से समझ चुके थे। इसलिए आईएएस बनने के बाद जब इन्हें राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में काम करने का अवसर दिया गया, तो अपने पुराने ग्रामीण क्षेत्र के अनुभवों के आधार पर इन्होंने विभिन्न जिलों में कलेक्टर पद पर रहने के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को समझना और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। हालांकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी अंतर जरूर है, लेकिन जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं की बात है, इस तरह की समस्याएं सभी प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान होती हैं। इसलिए राजेश यादव ने अब तक की अपनी आईएएस की नौकरी में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कल्याण और विकास तथा ग्रामीण क्षेत्र की खुशहाली के लिए खूब काम किया है। यहां तक की ग्रामीण क्षेत्र में विकास के संभावनाओं को तलाश कर ग्रामीण इलाकों को हाईटेक बनाने की दिशा में भी इनके काफी अच्छे प्रयास रहे हैं। इसलिए प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार, इन्हें प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर के रूप में काम करने का मौका दिया गया, ताकि सरकार की योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन भी हो और ग्रामीण क्षेत्र का समुचित रूप से विकास भी हो, जिसमें राजेश यादव हमेशा सरकार के विश्वास और भरोसे पर खरे उतरे।



रीजनल थर्ड आर एंड सर्कुलर इकोनामी फोरम के ऐतिहासिक आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर प्रदेश के नगर निकायों को गति देने का किया प्रयास

राजेश यादव पूर्व में जयपुर नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं, और जयपुर नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी पद के रूप में इनका कार्यकाल जयपुर नगर निगम के इतिहास में काफी अच्छा माना जाता है। बाद में वर्ष 2024 में राजेश यादव नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव पद पर नियुक्त हुए, तो अपने जयपुर नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर काम करने के दौरान जो अनुभव मिले थे, उनके आधार पर इन्होंने जयपुर नगर निगम ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी नगर निकायों में क्रांतिकारी बदलाव के लिए कई बड़े प्रयास किए। कई बड़े निर्णय के लिए, ताकि नगर निकायों की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होने के साथ-साथ कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई, बिजली, रोड सीवरेज इत्यादि आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किया। जिसमें जयपुर में रीजनल थर्ड आर एंड सर्कुलर

इकोनामी फोरम कार्यक्रम की शानदार तरीके से मेजबानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में 40 देश के करीब 500 डेलिगेट्स आए थे। इसके अलावा हिंदुस्तान के विभिन्न नगर निकायों के अध्यक्ष और प्रशासन से जुड़े बड़े अधिकारी इस विशेष कार्यक्रम में आए थे, जिसमें नगर निकायों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद, शोध पत्र इत्यादि का आयोजन हुआ था। जिसमें कचरा प्रबंधन और कचरे से ऊर्जा गैस इत्यादि पैदा करने जैसे विषयों पर गंभीरता से मंथन हुआ था। यह कार्यक्रम काफी सफल हुआ था, जिसमें जयपुर नगर निगम ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य नगर निकायों को भी काफी कुछ सीखने को मिला था। इसलिए राजेश यादव एक बहुमुखी प्रतिभा वाले आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। पूर्व में अशोक गहलोत सरकार में मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, जो यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति भी राजेश यादव की प्रशासनिक कुशलता और उनकी वर्किंग स्टाइल से काफी प्रभावित रहे हैं।



आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में अपना नंबर नहीं देख कर शॉक हो गए थे राजेश यादव



राजेश यादव ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा एक रोचक किस्सा सुनाते हुए बताया कि मेरी प्रारंभिक परीक्षा की बहुत ही अच्छी तैयारी थी, पेपर भी बहुत ही अच्छा हुआ था, इसलिए उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने की 100 प्रतिशत उम्मीद थी। उन्हें खुद पर पूरा कॉन्फिडेंट था, इसलिए जिस दिन रिजल्ट आया तो उनके दोस्तों ने उन्हें

रिजल्ट देखने को कहा। उस समय इस परीक्षा के अखबारों में रिजल्ट प्रकाशित नहीं होते थे, बल्कि संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर से बंडल के माध्यम से निश्चित जगह पर परीक्षा परिणाम भेजे जाते थे। जब दोस्तों ने कहा कि चलो रिजल्ट देखने चलते हैं, तो उन्होंने रिजल्ट देखने चलने के इनकार कर दिया। वजह यही थी कि उन्हें भरोसा था कि वह पास होंगे, लेकिन दोस्तों के बार-बार कहने के बाद वे दोस्तों के साथ रिजल्ट देखने के लिए लखनऊ चले गए। जहां कार्यालय में राजेश यादव ने परीक्षा परिणाम में अपना नंबर देखा तो नंबर नहीं मिला। यह देखकर वह काफी शॉक हो गए और कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। तभी उनके दोस्तों ने कहा कि चलो हम देखते हैं, और जब उनके दोस्तों ने परीक्षा परिणाम में यादव का नंबर देखा तो मिल गए। तब जाकर राजेश यादव को तसल्ली मिली, अन्यथा यादव यही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, उनका तो पूरा पेपर ही बहुत अच्छा गया था, फिर कैसे फेल हो गई कैसे फेल हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं राजेश यादव जब परीक्षा परिणाम देख रहे थे, तो वे ठीक तरह से जल्दी बाजी में रिजल्ट के पन्ने को नहीं देख पाए, इसकी वजह से उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई।

आईएएस बनने की तमन्ना दिल में कब और क्यों जागृत हुई?

जानकारी के अनुसार, राजेश यादव के पिता उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अधिकारी थे, इसलिए वे सरकारी दफ्तर में आयोजित होने वाली विभिन्न तरह की सरकारी मीटिंगों के कई रोचक किस्से अक्सर घर पर परिजनों के साथ शेयर किया करते थे, जिसमें कलेक्टर और कई बड़े अधिकारियों के साथ बिताए पलों का भी जिक्र किया करते थे। बड़े अधिकारियों के व्यक्तित्व, लाइफस्टाइल, बोलचाल, व्यवहार, काम करने के तरीके इत्यादि सबके बारे में परिजनों को बताया करते थे। उस समय राजेश यादव की स्कूलिंग हो रही थी, और वे अपने पापा के इन रोचक किस्सों को बहुत ही गंभीरता और चाव से सुना करते थे, जिसकी वजह से स्कूल की शिक्षा के दौरान ही इनके दिल और दिमाग पर अपने पापा के इन किस्सों का जबरदस्त प्रभाव पड़ गया था, जो इन्हें खुद एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करने लगा। बाद में कानपुर में बीटेक करने के दौरान ही समय-समय पर प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले, आईएएस के एग्जाम में सेलेक्ट होने वाले परीक्षार्थियों के साक्षात्कार पढ़कर, राजेश यादव इन टैलेंटेड अभ्यर्थियों की जीवनी, संघर्ष और पढ़ाई से खूब प्रभावित हुआ करते थे। खुद भी इन्हीं की तरह आईएएस बनने का ख्वाब देखने लग गए, और ख्वाब ही नहीं देख रहे थे, बल्कि अपने पिता की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आईएएस बनने का संकल्प भी लिया। इस संकल्प को भारतीय प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा के पहले ही प्रयास में पूरा करके भी दिखाया।



बीकानेर में करोड़ों की सरकारी जमीन को भू-माफिया से मुक्त करवाने वाली इस दबंग और ईमानदार अधिकारी के आगे आजकल खनन माफिया भी टेकने लगे घुटने, खान विभाग में व्हीकल ट्रेकिंग लोकेशन डिवाइस और रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करके अवैध खनन करने वालों की तोड़ दी है कमर। जालौर और बीकानेर में कलेक्टर पद पर रहने के दौरान जो उत्कृष्ट कार्य किया उन्हें लोग आज भी दिल से हैं लगाए हुए, वित्त विश्लेषण और बजट तैयार करने में भी विश्लेषण अधिकारी के रूप में मानी जाती है यह महिला अधिकारी।

सिंधम लेडीज आईएस नम्रता वर्षिनी का खनन माफिया पर चाबुक, सरकारी राजस्व को चोट पहुंचाने वालों की खैर नहीं

जयपुर। राजस्थान खनिज के क्षेत्र में पूरे देश में अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहां पर 85 तरह के विभिन्न खनिज प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मौजूद हैं। लेकिन यह भी सच है कि खनिज का दोहन करने में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में सालों से पीछे रहा, जिसकी वजह से प्रदेश की सरकारी तिजोरी में जितना पैसा खान विभाग की ओर से आना चाहिए था, उसमें से आधा पैसा भी तिजोरी में कई सालों से नहीं आ पा रहा था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि प्रदेश में प्रचुर खनिज संपदा को सालों से खनन माफिया लूट रहे थे, जिसका सरकारों को पता भी रहता था, लेकिन अपनी ऊंची राजनीतिक पहुंच, धनबल और भुजबल के आधार पर खनन माफिया बेखौफ होकर प्रदेश की खनिज संपदा को लूट रहे थे और हर साल प्रदेश सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का राजस्व का नुकसान भी पहुंचा रहे थे। लेकिन पिछले सवा दो साल में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने खान विभाग में एक तरफ जहां कई नवाचार और नए प्रयोग करके प्रदेश के खान विभाग की व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में

उत्कृष्ट कार्य किया, तो दूसरी तरफ खान विभाग में दबंग, ईमानदार और मेहनती उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करके खान विभाग को नई गति और दिशा देने की जोरदार पहल की है। जिसमें वर्तमान में खान विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर अपर्णा अरोड़ा और विशेष सचिव पद पर नम्रता वर्षिनी, जो अपनी ईमानदार छवि और अपनी शानदार वकिंग स्टाइल को लेकर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में छाई हुई है, इन दोनों महिला अधिकारियों को खान विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने काफी हद तक राजस्थान की प्रचुर खनिज संपदा को लूटने से बचा लिया है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में खान विभाग में व्हीकल ट्रेकिंग लोकेशन डिवाइस, जीपीएस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन जैसी नई व्यवस्थाओं का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करते हुए आधुनिक तकनीक का खान विभाग में भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे काफी हद तक प्रदेश में अवैध खनन करने वाले लोगों की गतिविधियों पर अंकुश लगा है। इन नई व्यवस्थाओं और नए प्रयोगों से अगर कोई चोरी छुपे प्रदेश की खनिज संपदा का दोहन और परिवहन कर रहा है, तो वह सीधे खान विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के बिल्कुल सामने नजर आने लगता है। क्योंकि खान विभाग से संबंधित सभी कार्यों को अब ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन तरीके से संपादित किया जाने लगा है, चाहे वैधखनन में अवैध खनन करने का विषय हो या फिर खनन परिवहन में लाए जाने जाने वाले सभी तरह के व्हीकल हो, इन सब की लोकेशन और गतिविधियों पर



खान विभाग के बड़े अधिकारियों की सीधी नजर रहती है। इसलिए थोड़ी सी भी गड़बड़ी और चोरी का भी खान विभाग के अधिकारियों को तुरंत पता लग जाता है, जिसकी वजह से सालों से प्रदेश की खनिज संपदा को लूट रहे खनन माफिया की अब एक तरह से दाल नहीं गल रही है। क्योंकि इन नवीन प्रयोग और नवाचारों से प्रदेश की खनिज संपदा को नुकसान पहुंचा रहे लोगों को मौके पर ही सबूत के साथ पकड़ लिया जाता है, और फिर खान विभाग की ओर से इनसे भारी भरकम जुर्माना और पेनाल्टी वसूल की जाती है, जिसकी वजह से अवैध खनन करने वालों की कमर टूट गई है। लेकिन यह भी कहना पड़ेगा कि खान विभाग में यह जो बड़ा क्रांतिकारी और अच्छा बदलाव आया है, इसमें खान विभाग की विशेष सचिव नम्रता वर्षिनी के अथक प्रयास और इस महिला अधिकारी की प्रभावी मॉनिटरिंग का बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। वैसे नम्रता वर्षिनी अपनी वर्किंग स्टाइल और दबंग छवि को लेकर पहले से ही काफी सुर्खियों में रही हैं। सबसे पहले जहां-जहां और जिन जिन डिपार्टमेंटों में इन्हें नियुक्ति दी गई, वहां नियम और कानून की पालना करवाने में इन्होंने बड़े बड़े भू माफिया और गैर कानूनी धंधे करने वाले लोगों को नाको चने चबाए हैं। इसलिए इनकी दबंगई और ईमानदारी से प्रभावित होकर ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन्हें खान विभाग में लेकर आए और अब इन्होंने अपनी मेहनत और कार्यों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भरोसा और विश्वास भी काफी हद तक जीत लिया है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ही प्रदेश के खान विभाग ने एक तरफ जहां करोड़ों

अरबों रुपये की खनिज संपदा को लूटने से बचाया है, तो दूसरी तरफ अवैध खनन करने वालों से भारी भरकम पेनाल्टी वसूल करके प्रदेश सरकार की तिजोरी को भरा जा रहा है। इसलिए वर्ष 2013 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी नम्रता वर्षिनी अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक तरफ जहां भजनलाल सरकार में सुर्खियां बटोर रही हैं, तो दूसरी तरफ खान माफिया पर धड़ाधड़ सरपट चाबुक चल रही हैं, जिसके कारण खनन माफिया में खलबली मची हुई है।

बीकानेर कलेक्टर रहने के दौरान भी नम्रता वर्षिनी ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को भू माफिया से करवाया था मुक्त

जानकारी के अनुसार नम्रता वर्षिनी ने बीकानेर में कलेक्टर पद पर रहने के दौरान अपने कार्यकाल में कई बड़े-बड़े उल्लेखनीय काम किए थे, जिसमें एक बड़ा काम उनका यह भी रहा कि बीकानेर शहर के बीचो-बीच करोड़ों रुपये की लंबी चौड़ी सरकारी जमीन पर भू माफिया ने दबंगई से एक बड़ी कॉलोनी के प्लॉट बड़ी संख्या में काट दिए थे। लेकिन इस कॉलोनाइजर की राजनीतिक पहुंच और सेटिंग की नीति की वजह से कोई भी इसकी गैर कानूनी गतिविधि के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था और ना ही कोई प्रशासनिक एक्शन ले रहा था। लेकिन जैसे ही यह मामला नम्रता वर्षिनी की निगाहों में आया, इस महिला अधिकारी ने बेखौफ होकर गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर कॉलोनी विकसित करने के लिए भूखंड काट रहे भू माफिया के खिलाफ ठोस कागजी प्रक्रिया संपादित करते हुए अरबों रुपये कीमत की करीब 400 एकड़ जमीन को मुक्त करवाया, जिसकी चर्चा उन दोनों भी खूब हुई। और आज भी बीकानेर के लोग इस कार्रवाई के लिए नम्रता वर्षिनी की बहादुरी को याद करते हैं, क्योंकि भू माफिया से आजाद करवाई गई जमीन पर बीकानेर शहर के लोगों के लिए एक विशाल खूबसूरत पार्क विकसित करने का प्लान नम्रता वर्षिनी ने हाथों हाथ ही तैयार कर लिया था। इस जमीन पर कबीर वाटिका के नाम से एक खूबसूरत पार्क आज भी मौजूद है, लोग जब इस पार्क में घूमने आते हैं तो यहां रोमांचित होकर नम्रता वर्षिनी की बहादुरी और दिलेरी को खूब याद करते हैं।

करीब 1 लाख बच्चों के चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन करके चाचा नेहरू की तरह बच्चों में हुई लोकप्रिय



जानकार लोगों का कहना है कि बीकानेर जिले के सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चे आज भी नम्रता वर्षिनी को खूब मिस करते हैं, क्योंकि बीकानेर में कलेक्टर पद पर रहने के दौरान बच्चों से बेहद प्यार करने वाली इस महिला अधिकारी ने बीकानेर में एक ऐतिहासिक चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन करवाया था। इसमें बीकानेर की शहर और पूरे जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एक ही जाजम पर एकत्रित किया गया था। इस फेस्टिवल के माध्यम से नम्रता वर्षिनी ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीब निर्धन और किसानों के बच्चों के जीवन में उमंग और उत्साह लाने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया था, क्योंकि शहरी बच्चे तो शहरी जीवन में अपने आसपास बच्चों से जुड़ी सुविधाओं और मनोरंजन के साधनों का आनंद ले लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को यह सब नसीब नहीं होता। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में उमंग उत्साहित तथा रोमांचित करने के लिए बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक तरीके से चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों के मनोरंजन से संबंधित सभी सुविधा यंत्र उपकरण के अलावा बच्चों के ज्ञानवर्धन से जुड़ी विशेष सामग्री, विज्ञान पार्क इत्यादि सभी सुविधाएं सुनिश्चित की गई

थी, जिन्हें देखकर बच्चे काफी रोमांचित और आनंदित हुए थे। यह चिल्ड्रन फेस्टिवल बीकानेर के शिक्षा जगत के इतिहास में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। इस फेस्टिवल के चर्चे भी कई दिनों तक बीकानेर के शहरी और ग्रामीण लोगों की जुबान पर छाए रहे। जिले के विभिन्न दलों के राजनेताओं, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संगठनों ने भी इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए नम्रता वर्षिनी को थैंक्स कहा था। इस ऐतिहासिक चिल्ड्रन फेस्टिवल के बाद जिलों के बच्चों में नम्रता वर्षिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह काफी लोकप्रिय और पॉपुलर बन गई थी, उनके बच्चों के प्रति इतने असीम प्रेम को देखकर जिले के लोग भी इन्हें आज खूब याद करते हैं।

वित्त विशेषज्ञ और राजस्थान सरकार का बजट तैयार करवाने में भी माहिर मानी जाती है



नम्रता वर्षिनी पूर्व में वित्त विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं और वित्त विशेषज्ञ के रूप में इन्हें अच्छी पहचान मिली हुई है। इसीलिए प्रदेश का बजट तैयार करवाने में भी इनकी कई बार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले गहलोत सरकार के दौरान भी बजट तैयार करवाने में इनकी काफी अच्छी भूमिका रही थी, और वर्तमान में प्रदेश की भजनलाल सरकार के पहले कार्यकाल में बजट का ड्राफ्ट तैयार करवाने में भी नम्रता वर्षिनी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। प्रदेश की सरकार की तिजोरी में पैसा कैसे और किस तरह से ज्यादा से ज्यादा आए, और पैसे का किस तरह से और कैसे अच्छा सदुपयोग हो, तथा घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रम को कैसे और किस तरह से फायदा में लाया जाए, इन सब विषयों के बारे में नम्रता वर्षिनी को अच्छा नॉलेज है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मामले में इन्हें कुशल अधिकारी के रूप में माना जाता है, इसीलिए सरकार का बजट तैयार करवाने में कई बार इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

बीकानेर शहर और ग्रामीण इलाकों में कई किलोमीटर तक पैदल भ्रमण कर जिले के लोगों के दिलों में बनाया अपना अलग मुकाम



जानकार लोगों का कहना है कि बीकानेर जिलाधीश कार्यालय के इतिहास में यह पहला अवसर था, जब किसी कलेक्टर ने कई किलोमीटर तक शहरी और ग्रामीण इलाकों में पैदल चलकर लोगों की समस्याओं को सुन कर उनका निदान करवाया हो और क्षेत्र के विकास के कार्यों का तेजी से आगे बढ़ाया हो। जी हां, नम्रता वर्षिणी ने बीकानेर में कलेक्टर पद पर रहने के दौरान बीकानेर पुलिस अधीक्षक के साथ कई कई किलोमीटर पैदल चलकर लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण भी करवाया। इसके अलावा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, वृक्षारोपण, कानून व्यवस्था, पानी बिजली इत्यादि सभी व्यवस्थाओं और सुविधाओं को मौके पर जाकर अपनी आंखों से देखा, और जहां भी जिस भी चीज की कोई कमी और लापरवाही नजर आई तो उसे तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारियों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। उनका यह पैदल भ्रमण मीडिया की सुर्खियों में भी कई दिनों तक बना रहा, क्योंकि उनकी यह पैदल यात्रा बीकानेर शहर तक की सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने बीकानेर के दूर दराज के इलाकों में भी पैदल चलकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण का प्रयास किया। जानकार लोगों का कहना है कि नम्रता वर्षिणी की कठिन मेहनत और ईमानदारी से समर्पित भाव से काम करने की हैबिट को देखकर ही सरकार ने इन्हें सिर्फ कलेक्टर पद की ही जिम्मेदारी नहीं दी, बल्कि एक साथ बीकानेर में कई महत्वपूर्ण

जिम्मेदारियां उनके हाथों में दी, ताकि बीकानेर प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ सके। सरकार ने नम्रता वर्षिणी के हाथों में कलेक्टर पद की जिम्मेदारी के अलावा बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर डिविजनल कमिश्नर जैसे बड़े पदों की जिम्मेदारी भी दी। इसके अलावा कमांड एरिया में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने और नहरी पानी के समुचित वितरण की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी इन्हें दी गई। इसके अलावा बीकानेर जिले की सीमा पाकिस्तान की सीमा से जुड़ी हुई है, इसलिए सीमावर्ती इलाके में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और पाकिस्तान से अवैध मादक पदार्थ तथा हथियारों की तस्करी के मामलों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए इन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई, जिसमें नम्रता वर्षिणी ने समय-समय पर बीएसएफ और पुलिस के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक आयोजित करके जिले की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में लगातार काम करती रही। इसके अलावा बीकानेर जिले में पाताल तोड़ कुआं अभियान को भी इन्होंने सफलतापूर्वक संपादित किया तथा जिले में बरसात के पानी का ठीक तरह से संरक्षण हो तथा जिले में भूजल स्तर ऊंचा हो, इसके लिए भी इनकी ओर से किए गए कार्य और प्रयास काफी बेमिसाल रहे, जिसकी वजह से बीकानेर जिले में भूजल का स्तर काफी ऊंचा उठा। इसके अलावा केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से संचालित की जा रही विभिन्न तरह की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए इन्होंने नियमित रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारी से संवाद बनाए रखा और समय-समय पर सभी योजनाओं एक क्रियान्वयन और विकास कार्यों का नियमित रूप से संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लेती रही। जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी इनके कलेक्टर पद पर रहने के दौरान बीकानेर प्रदेश भर में आगे रहा। इस तरह से बीकानेर में कलेक्टर के रूप में इनका कार्यकाल बीकानेर के गलियारों में काफी ऐतिहासिक माना जाता है।



जालौर में छात्र-छात्राओं के हेल्थ शिक्षा और खेल इत्यादि क्षेत्र में किए उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य



नम्रता वर्षिनी पूर्व में जालौर जिले की कलेक्टर भी रह चुकी हैं। जालौर जिला प्रदेश का ऐसा जिला है जहां आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं और साक्षरता का प्रतिशत भी अन्य जिलों की तुलना में काफी कम है। इसलिए जिले में छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा जैसे विषयों पर नम्रता वर्षिनी ने काफी प्रभावशाली काम किया। जिसमें स्कूलों में बालिकाओं के हेल्थ के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित करवाए गए, बालिकाओं को शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए समय-समय पर शिविरों का आयोजन करवाया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ उन्हें आवश्यक दवाइयां और पौष्टिकभोजन संबंधी टिप्स भी दिए गए। इसके अलावा नम्रता वर्षिनी को जब यह जानकारी मिली कि सरकार की ओर से छात्राओं को दी गई स्कूटी का छात्राएं उपयोग नहीं करके उनके परिवार वाले स्कूटी का उपयोग करते हैं, तो उन्हें काफी बुरा लगा। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा जो छात्राएं 18 साल की हो चुकी थी, उन्हें ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिलाने के लिए अभियान शुरू किया ताकि छात्राएं खुद स्कूटी की ड्राइविंग कर सकें, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए और छात्राएं खुद स्कूटी ड्राइविंग करके स्कूल आने लगी। इसके अलावा जिले में विभिन्न तरह के खेलों का अच्छा प्लेटफार्म तैयार करने और अच्छे प्लेयर तैयार करने के लिए भी कलेक्टर के रूप में इन्होंने काफी अच्छा काम किया, जिसमें वृशु गेम्स के क्षेत्र में इन्होंने काफी शानदार और उत्कृष्ट कार्य किया। इसके लिए ग्राउंड और अन्य सभी व्यवस्थाओं को काफी मजबूत किया गया, इसके बाद इस गेम्स में जालौर जिले के प्लेयर रूस और अन्य देश में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से जालौर जिले में भी कलेक्टर के रूप में

इनके कार्यों को आज भी लोग याद करते हैं। जालौर जिले में भी इन्होंने अपने आवास और सरकारी दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे सबके लिए खुले रखे थे। इसके अलावा जालौर में भी इन्होंने नियमित रूप से लोगों से संवाद बनाए रखा, जनसुनवाई और जनता दरबार जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करके जिले के लोगों की तकलीफों को दूर करने और सरकार की योजनाओं को सतत रूप से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के कार्य को प्रभावी तरीके से संपादित करवाया। इसलिए जालौर जिले के लोग भी इनके कामों को और अच्छे व्यवहार को आज भी याद करते हैं।

हाई प्रोफाइल परिवार से ताल्लुक होने के बाद भी बहुत सिंपल और अपने नाम के मुताबिक सरल और सहज स्वभाव की है यह महिला अधिकारी



जानकारी के अनुसार नम्रता वर्षिनी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिलेक्ट होने से पहले करीब 4 साल तक आईआरएस में सेवाएं दी, लेकिन आईआरएस में काम करने का सीमित दायरा था और यह महिला अधिकारी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में काम करके लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहती थी। इसलिए अपने विजन और दिल की तमन्ना को पूरी करने के लिए इन्होंने वर्ष 2012 में आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा भारती की परीक्षा में सफलता हासिल की और इन्हें राजस्थान में काम करने का अवसर दिया गया। बड़ी बात यह है कि एक हाई प्रोफाइल परिवार में जन्म लेने के बाद भी नम्रता स्वभाव से काफी सरल और सहज दिखती हैं। लोग कहते हैं कि जैसा इनका नाम नम्रता है, वैसे ही दिल की भी काफी सहज सरल और मधुर हैं, जो इनकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देते हैं। हालांकि नियम और कानून को फॉलो करवाने में इनका काफी कड़क मिजाज और रवैया रहता है, लेकिन आमजन से मुलाकात के दौरान हमेशा खुले दिल से और तसल्ली से संवाद करती हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति ठीक तरह से अपनी समस्या और अपनी बात बता सके। इनका बोलचाल और व्यवहार आम लोगों से बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए प्रदेश में कलेक्टर रहने को दौरान भी इनका पब्लिक से बहुत अच्छा चुनाव रहा। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली नम्रता वर्षिनी के पिता जज और इनका एक भाई अतिरिक्त जज और एक भाई प्रोफेसर है। इसलिए नम्रता वर्षिनी भी पढ़ाई में शुरू से ही काफी इंटेलिजेंट थी, इसलिए दिल्ली की श्रीराम लेडी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ किया। इनके पति भी भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं।

राजस्व मंडल में रजिस्ट्रार और बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी को भी शानदार ढंग से निभाया



जानकार लोगों का कहना है कि राजस्व मंडल में रजिस्ट्रार जानकार लोगों का कहना है कि राजस्व मंडल में रजिस्ट्रार पद पर रहने के दौरान नम्रता वर्षिनी ने आधुनिक तकनीक और राजस्व मंडल के कामकाज को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन तरीके से संपादित करवाने की प्रक्रिया पर गंभीरता से काम किया, ताकि लोगों की समस्याओं और कार्यों का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो सके। नम्रता वर्षिनी ने जमीन से जुड़े तमाम तरह के कामकाज, राजस्व रिकॉर्ड और लेखा-जोखा सब कुछ ऑनलाइन और आधुनिक तरीके से संयोजित करने की प्रक्रिया पर ज्यादा फोकस किया, ताकि राजस्व मंडल में चल रहे विवादित मामलों का निस्तारण की प्रक्रिया को भी संबल मिल सके। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड को आधुनिकरण करने का प्रभावी प्रयास किया गया जिसके अच्छे नतीजे भी आए। इसी तरह से नम्रता ने बीकानेर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर काम करने के दौरान भी जिले की एक-एक ग्राम पंचायत के कामकाज और बजट पर पूरा फोकस रखा। ग्राम पंचायत के विकास के लिए जारी होने वाला सरकारी पैसा

ग्राम पंचायत के विकास में ही काम आए, इस प्रक्रिया पर उनकी हमेशा सतत रूप से नजर रही, और लगातार एक-एक ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का फीडबैक और लेखा-जोखा लिया ताकि ग्राम पंचायत के बजट पर कोई बुरी नजर नहीं डाल सके। जानकार लोगों का कहना है कि इन तीन बड़े जिलों में जिला परिषद में कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने के दौरान इस महिला अधिकारी को ग्रामीण जनता और ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को समझने का नजदीकी से अवसर मिला। इस अनुभव और अवसर को अब तक नम्रता वर्षिनी अपने दिल में बसाए हुए हैं और हमेशा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की हितों की रक्षा और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नया करने के लिए तैयार रहती हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी के शुरुआती के दिनों में नम्रता उदयपुर जिले में गिरवा में एसडीएम पद पर भी रही हैं, इसके अलावा प्रदेश में एडिशनल कलेक्टर के रूप में भी काम किया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2013 से लेकर अब तक का इनका यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2013 से लेकर अब तक का इनका आईएएस की नौकरी का यह सफर काफी शानदार और बेमिसाल रहा है। जिसमें एक बार भी इनकी कार्य प्रणाली और इनकी ईमानदारी को लेकर कभी भी किसी ने कोई सवाल खड़े नहीं किया, बल्कि जहां भी और जिस भी पोस्ट पर रही, वहां इन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों और अपने अच्छे व्यवहार से सब का दिल जीता।





बजरी माफिया, नशे के कारोबारी और गैंगस्टर के जानी दुश्मन तो युवाओं के जानी दोस्त आईपीएस “राजर्षि राज वर्मा”

जयपुर। समाज में वे दंपति सबसे ज्यादा सफल और लोकप्रिय होते हैं, जो एक दूसरे के विचारों और परिस्थितियों को समझते हुए कठिन से कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला करते हैं और दोनों हर कठिन मुश्किल को हंसते-हंसते पार कर लेते हैं। जिसमें अगर पति और पत्नी दोनों ही हाई प्रोफाइल सरकारी सर्विस में हो, जिसमें अगर दोनों ही आईपीएस हो, तो फिर बात ही निराली हो जाती है। दोनों की सक्सेसफुल जीवन की यात्रा मेट्रो ट्रेन की रफ्तार से दौड़ती रहती है और दोनों का समाज में बड़ा सम्मान तो होता है ही, इसके अलावा लाखों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा के स्रोत भी बन जाते

जोधपुर में लूनी और टोंक में बनास नदी से अवैध बजरी खनन करने वाले माफिया को छठी का दूध याद दिलाने वाले इस दबंग आईपीएस अफसर ने नशे का कारोबार करने वाले बड़े-बड़े माफिया को नाको चने चबाया। अपनी बेहतरीन लाइफ स्टाइल और वर्किंग स्टाइल से लाखों युवाओं के बने हैं प्रेरणा के स्रोत। टोंक, जोधपुर, झुंझुनू, डूंगरपुर जिलों में हर तरह के अपराधों पर लगाम लगाने और पुलिसिंग को नई दिशा और गति देने में निभा चुके हैं महत्वपूर्ण भूमिका। वर्तमान में जयपुर साउथ में डीसीपी की भूमिका को शानदार ढंग से निभाते हुए शहर में हर तरह के क्राइम के ग्राफ को ला रहे हैं तेजी से नीचे। गुजरात कैडर की अपनी आईपीएस पत्नी के पुश करने से आईपीएस बने, 2017 बैच के इस अफसर के हाथों से लिखी पुस्तक “इंटरनल सिक्वोरिटी” को देश और दुनियाभर के लोग कर रहे हैं पसंद। इस अफसर की वर्किंग स्टाइल और जीवन संघर्ष की गाथा पर बन सकती है सुपर डुपर एक्शन फिल्म।

हैं। जैसे भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान केडर के अधिकारी राजर्षि राज वर्मा और उनकी गुजरात कैडर की आईपीएस पत्नी शेफाली बरवाल। इन दोनों के बीच आपस में जो बेहतरीन समन्वय और एक दूसरे की परिस्थितियों और विचारों को समझने और एक दूसरे का सम्मान करने का जो भाव है, वह निश्चित रूप से दिल को छू लेने वाला है। जो समाज में उन पति पत्नी के लिए सीख लेने की बात बन जाती है, जो छोटी-छोटी बात पर या नौकरी और कारोबार की मजबूरी से एक दूसरे को पर्याप्त समय नहीं देने के लिए आपस में शिकायत करते-करते दोनों अलग होने का रास्ता चुन लेते हैं, जिसका दर्द उन्हें जीवन भर झेलना पड़ता है। आज हम इस आर्टिकल में सिर्फ बात करेंगे राजर्षि राज वर्मा की, जो वर्तमान में जयपुर डीसीपी साउथ पद पर पोस्टेड है, जिनकी अब तक की 9 साल की आईपीएस की सर्विस की यात्रा का सफर पुलिस के रिकॉर्ड में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में लिखा जा चुका है। जिन्होंने वर्तमान में जयपुर में अपने क्षेत्र में छोटे-बड़े सभी तरह के अपराधों को रोकने में काफी हद तक सफल हुए हैं, और अगर कोई बड़ी क्राइम की घटना हुई भी है, तो उसका खुलासा भी जल्दी ही किया है और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया है।



मजबूत बीट व्यवस्था पर सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं राजर्षि राज वर्मा

जानकारी के अनुसार, राजर्षि राज वर्मा प्रदेश में वर्ष 2017 में आईपीएस के लिए सिलेक्ट होने के बाद शुरुआती दिनों में उदयपुर, बांसवाड़ा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त रहे, जयपुर पूर्व में भी एडीसीपी पद पर नियुक्त रहे। इसके अलावा टोंक, झुंझुनू, डूंगरपुर जिलों में एसपी पद पर रहे, साथ-साथ जोधपुर पश्चिम के डीसीपी रहे। इस तरह से राजस्थान में अपने 9 साल के सर्विस काल में इनकी दबंग छवि और कड़ी मेहनत तथा ईमानदारी से काम करने की प्रवृत्ति को देखते हुए, प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, इन्हें फील्ड पोस्टिंग ज्यादा दी गई। जिसमें हर जिले में इन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करके अपराध जगत से जुड़े लोगों में अपने नाम का डर बैठाया। आज बड़े से बड़ा गैंगस्टर ग्रुप से जुड़ा बदमाश राजर्षि राज वर्मा का नाम सुनते ही चुपचाप बिल में दुबकता हुआ दिखाई देने लगता है, क्योंकि इन्होंने झुंझुनू जैसे बड़े संवेदनशील जिले जहां पर कई बड़े-बड़े कुख्यात

बदमाशों के विशाल ग्रुप बने हुए थे, वहां पर एसपी पद पर रहने के दौरान बड़ी संख्या में बड़े-बड़े ग्रुप से जुड़े बदमाशों को गिरफ्तार किया और प्रभावी कार्रवाई करके उनकी संपत्तियों को भी अटैच करने की प्रभावी कार्रवाई की। इसलिए झुंझुनू जिले में इनके काम करने के तरीकों और इनकी कार्रवाइयों को आज भी जिले के लोग काफी याद करते हैं। वैसे तो इस आईपीएस अधिकारी के बारे में कहा जाता है कि शांति और कानून व्यवस्था से जुड़े छोटे से छोटे विषय पर भी गंभीरता से काम करते हैं, इसके अलावा चाहे अपराध छोटा हो या बाद हर अपराध को गंभीरता से लेते हुए उस पर प्रभावी तरीके से काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। यही वजह रही की राजधानी जयपुर में भी मानसरोवर और विधायक पुरी जैसे इलाकों में लाखों रुपए की हुई बड़ी चोरियों का बहुत जल्दी ही खुलासा करके अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया। इसी तरह से साइबर क्राइम और जमीन से जुड़े मामलों की जांच प्रक्रिया पर भी खुद निगरानी रखते हैं, विभिन्न पुलिस स्टेशन में दर्ज होने वाले सभी तरह के मामलों की जांच प्रोसेस का नियमित रूप से अपडेट लेते रहते हैं। इसके अलावा जयपुर में भी नियमित रूप से होटल, धर्मशाला, मदरसा इत्यादि का निरीक्षण करना, खुफिया तंत्र के विस्तार और मजबूती के विषय पर भी लगातार काम करते रहते हैं। साथ-साथ बीट व्यवस्था पर अपना सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि अगर बीट व्यवस्था मजबूत होती है, तो फिर निश्चित रूप से या तो इलाके में अपराध होंगे ही नहीं, या फिर इलाके में अगर कोई बड़ी क्राइम की घटना या अशांति जैसा माहौल होने की स्थिति बन सकती है, ऐसे समय में मजबूत बीट व्यवस्था और मजबूत खुफिया तंत्र के इनपुट के आधार पर पुलिस समय से पहले ही प्रभावी कार्रवाई और तैयारी कर लेती है, जिसकी वजह से बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए थाना स्तर पर बीट व्यवस्था को मजबूती करने के विषय पर राजर्षि राज वर्मा ने हमेशा विशेष प्रयास किया और कदम उठाए, जिसकी वजह से हमेशा इनकी परफॉर्मेंस हर जिले में काफी शानदार और उत्कृष्ट रही। जयपुर साउथ में भी इनकी पोस्टिंग के समय से लेकर अब तक विभिन्न तरह के अपराध के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हर तरह के अपराध में तेजी से गिरावट आ रही है। इसलिए इनके बेस्ट सुपरविजन और नियमित रूप से थाना स्तर पर पर प्रत्येक मामले से जुड़े विषय और कामकाज का फीडबैक लेने की अपनी प्रवृत्ति से राजर्षि राज वर्मा ने खुद को एक श्रेष्ठ, दबंग, ईमानदार और अनुशासित अधिकारी के रूप में स्थापित किया हुआ है। इनके परफॉर्मेंस से पुलिस मुख्यालय और राजस्थान का गृह विभाग भी काफी खुश और प्रभावित है।

लेखक के रूप में भी एक बेहतर लेखक के रूप में अपनी पुस्तक "इंटरनल सिक्योरिटी" को लेकर भी काफी सुर्खियों में है राजर्षि राज वर्मा



जानकारी के अनुसार, राजर्षि राज वर्मा कॉफी हाई प्रोफाइल पढ़ाई किए हुए हैं। इन्होंने दिल्ली की किरोड़ीमल कॉलेज से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की और एमबीए भी किया। इस तरह से मैनेजमेंट के मामले में इनकी शुरू से ही काफी दिलचस्पी रही, इसीलिए इन्होंने मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया, पुलिस मैनेजमेंट में भी इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। इन तमाम खूबियां के अलावा लिखने का इन्हें शुरू से ही चाव रहा है। जीवन में मिलने वाले अनुभव, विशिष्ट व्यक्तियों से हुई बातचीत से निकलने वाले विशेष निष्कर्ष, ट्रेनिंग और पुलिस की नौकरी के दौरान मिले विशेष अनुभव, इन सबको अपनी लाइफ में एक बड़ी सीख के रूप में लेते हैं, और फिर इन अनुभवों से शब्दों की लिखित माला तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से इन्होंने एक प्रभावी पुस्तक 'इंटरनल सिक्योरिटी' पुस्तक लिखी, जो राजस्थान और देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में काफी पॉपुलर हो रही है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए काम कर रही सरकारी संस्थाएं और निजी क्षेत्र के लोग पुस्तक को बड़े गंभीरता से पढ़ते हैं। हालांकि पुस्तक को राजर्षि राज वर्मा ने इंग्लिश में लिखा है, जिसका अब हिंदी अनुवाद भी किया जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में यह पुस्तक हर किसी के लिए काफी सहायक साबित हो सकती है, इसीलिए इस पुस्तक की डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। राजर्षि राज वर्मा ने कहा है कि इसका अगला संस्करण भी जल्दी ही लिखेंगे। इसके लिए अगर

कोई अपना सुझाव और अपनी सलाह देना चाहे तो उन्हें दे सकते हैं, जिसको अपनी पुस्तक में जरूर जगह देंगे। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक प्रदेश और देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें राजस्थान और भारत जैसे देश के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का और भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि राजस्थान के पांच जिलों की सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। इसी तरह से हमारे देश की सीमा भी कई देशों से जुड़ी हुई है, इसलिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करणी की दिशा में सतत रूप से निगरानी और काम करने की जरूरत है।

मिशन संकल्प अभियान से लाखों छात्र छात्राओं और युवाओं का बेहतर भविष्य बनाने के लिए शानदार प्लेटफॉर्म बनाया

जानकारी के अनुसार, जोधपुर में डीसीपी पद पर रहने के दौरान जोधपुर और आसपास के जिलों में अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राजर्षि राज वर्मा ने मिशन संकल्प अभियान का शुभारंभ किया था। यह अभियान बीकानेर और आसपास के जिलों में जो छात्र-छात्राएं और युवा नशे की लत से लगातार जुड़ रहे थे, उनके लिए यह अभियान वरदान बन क्योंकि इस अभियान के माध्यम से राजर्षि राज वर्मा ने एक तरफ जहां नशे का कारोबार कर रहे लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और नशे का कारोबार करने वाले लोगों की संपत्तियों को अटैच करने तक की प्रभावी कार्रवाई की, तो दूसरी तरफ स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों इत्यादि की मदद से जोधपुर और आसपास के जिलों में नशे से दूर रहने के लिए व्यापक स्तर पर जन जागृति अभियान को संपादित करवाया, जो काफी हद तक युवाओं के लिए लाभदायक रहा। जो युवा नशे के आदी हो रहे थे, उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाया गया और उनका ट्रीटमेंट करवा कर उन्हें बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके लिए राजर्षि राज वर्मा ने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में ज्यादा से ज्यादा शिविर, सेमिनार इत्यादि का आयोजन करके, विशेषज्ञ लोगों के लेक्चरर्स करवा कर, छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें काफी सफलता भी मिली। इसीलिए आज भी इस अभियान को लेकर जोधपुर के लोग राजर्षि राज वर्मा को काफी मिस कर रहे हैं।

टोंक में बनास और जोधपुर में लूनी नदी में बजरी खनन करने वालों का पूरी तरह से कर दिया था सफाया

जानकारी के अनुसार, राजर्षि राज वर्मा जब टोंक जिला पुलिस अधीक्षक बने, यह पहला मौका था जब इन्हें किसी जिले का एसपी बनाया गया। इसलिए किसी भी आईपीएस के लिए पुलिस अधीक्षक के रूप में पहली बार किसी जिले में पोस्टिंग मिलना उसकी लाइफ का एक अलग पाठ बन जाता है, जिसे वह जीवन भर नहीं भूलता है। इसलिए टोंक जैसे संवेदनशील जिले में ही किसी जिले के एसपी के रूप में पहली बार पोस्टिंग होना राजर्षि राज वर्मा के लिए बड़ी चुनौती की तरह थी, क्योंकि टोंक जिला अवैध खनन और बजरी खनन के लिए सालों से राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी बना हुआ था और राजस्थान हाई कोर्ट भी कई बार अवैध खनन और बजरी खनन को लेकर सरकार और पुलिस को फटकार लगा चुका था। इसके अलावा टोंक जिले में सांप्रदायिक तनाव जैसे हालात भी कई बार देखने को मिल जाते हैं, इसलिए राजर्षि राज वर्मा के सामने बड़ी-बड़ी चुनौती और बड़े-बड़े विषयों पर काम करने की जरूरत थी। जिस पर यहां एसपी पद पर रहते हुए, राजर्षि राज वर्मा ने करीब 1 साल के कार्यकाल में टोंक जिले में बनास नदी से अवैध बजरी खनन करने वालों का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। अवैध खनन करने वालों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष रणनीति और प्लान तैयार करके उसे बेहतरीन तरीके से क्रियान्वित किया गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर अवैध बजरी से भारी वाहन बरामद किए गए और अवैध खनन करने वालों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। यहां तक की संपत्ति जप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। इसी तरह से टोंक जिले में करीब 1 साल के कार्यकाल में राजर्षि राज वर्मा ने विभिन्न धर्म और समाज के लोगों के बड़े लोगों से लगातार संवाद जारी रखा, शांति व्यवस्था के लिए प्रेरित करते रहे और पुलिस के खुफिया तंत्र को भी निचले स्तर पर प्रभावी और मजबूती देने की व्यवस्था की। जिसकी वजह से खुफिया तंत्र से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस पहले ही किसी भी बड़ी घटना

को रोकने के लिए पूरे प्रबंध कर लेती थी। इस तरह से इनके कार्यकाल में टोंक जिले में कभी भी सांप्रदायिक झगड़ा जैसी बात सामने नहीं आई। इसी तरह से जोधपुर पश्चिम डीसीपी पद पर रहने के दौरान लूनी नदी में अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ टोंक की तरह ही प्रभावी कार्रवाई की, और दो सप्ताह के अंदर ही अपने कुशल प्रबंधन और बेहतरीन प्लानिंग से लूनी नदी में व्यापक पैमाने पर हो रहे अवैध बजरी खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया था। यहां पर राजर्षि राज वर्मा ने बड़े पैमाने पर चेक पोस्ट का गठन किया था, और एक विशेष पुलिस की विंग की स्थापना करके यहां बजरी खनन करने वालों को चिन्हित किया गया और बजरी से भरे कई विकल बरामद किए गए। पकड़े गए बजरी माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, यहां भी माफिया की संपत्ति अटैच करने तक की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसलिए आज भी अवैध खनन और बजरी का अवैध कारोबार करने वाले लोगों में राजर्षि राज वर्मा के नाम से काफी डर बैठा हुआ है।

हर प्रॉब्लम का समाधान होता है क्योंकि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं

आईपीएस राजर्षि राज वर्मा का कहना है कि सतत रूप से ईमानदारी और मेहनत से कर्म करते रहना चाहिए, ईश्वर भी उन लोगों की मदद करता है जो कर्म करते हैं। राजर्षि राज वर्मा का कहना है की सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, असफलताओं से सीख कर ही सफल होने का एक अलग मजा होता है। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान होता है, क्योंकि शुद्ध मन से तपस्या करने से जब भगवान मिल जाते हैं, तो फिर दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं हो। इनका कहना है कि पुलिस में नौकरी के दौरान भी मेरा पूरा फोकस इसी बात पर रहता है कि कुछ ऐसे इंतजाम और प्रबंध किए जाएं ताकि अपराध की घटना हो ही नहीं, और अगर अपराध की घटना हो भी जाती है, तो दोबारा से इस तरह का अपराध नहीं हो, इस पर गंभीरता से काम करने की सोचता हूं। तथा जिसने अपराध किया, उसे सबक सिखाने और यह एहसास दिलाने के लिए कि उसने गलत किया है, उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाने की कोशिश करता हूं।



जयपुर की आईपीएस बेटी पर आया दिल और बनाया अपना जीवन साथी



राजर्षि राज वर्मा मुख्य रूप से बिहार के रहने वाले हैं और वर्ष 2017 बीच के आईपीएस अधिकारी हैं। इनकी पत्नी शेफाली बरवाल जयपुर की ही रहने वाली हैं और वर्ष 2016 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की गुजरात केडर की अधिकारी हैं। दोनों ट्रेनिंग के दौरान ही एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को दिल भी दिया और फिर आपस में जीवन साथी भी बन गए। इस तरह से इस दबंग अधिकारी का खूबसूरत शहर से गहरा दिल का रिश्ता बन गया है, जयपुर अब इनका ससुराल बन चुका है। दोनों के एक प्यारा बेटा और एक प्यारी बेटी हैं। भले ही दोनों वर्तमान में अलग-अलग स्टेट में पोस्टेड हो, लेकिन दोनों के बीच बहुत ही बेहतर समन्वय और सामंजस्य बना हुआ है और दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों और स्थितियों को समझते हुए, परिवार और नौकरी से जुड़ी हर प्रॉब्लम को हंसते-हंसते शार्ट आउट कर लेते हैं, इसलिए दोनों की बहुत ही खुशहाल जिंदगी है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सर्विस की जिम्मेदारी को भी बहुत ही खूबसूरती और प्रभावी तरीके से निभा रहे हैं। दोनों की वर्किंग स्टाइल, कड़ी मेहनत और समर्पित भाव से काम करने के अपने अंदाज से, अपने-अपने स्टेट की सरकारों की निगाहों में भी सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के रूप में माने जाते हैं और पब्लिक फेस में भी अपनी अपनी जगह पर पॉपुलर रहे हैं। इसीलिए इस

आईपीएस दंपति की चर्चा राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी और राजस्थान पुलिस मुख्यालय में ही नहीं, बल्कि गुजरात की ब्यूरोक्रेसी और गुजरात पुलिस मुख्यालय में भी होती रहती हैं।

प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्र के एडीसी पद पर भी नियुक्त रहे

राजस्थान में वर्ष 2019 से 2024 तक राज्यपाल रहे कलराज मिश्र के एडीसी के रूप में भी राजर्षि राज वर्मा ने जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान तत्कालीन राज्यपाल मिश्र के साथ देश और दुनिया में कई जगहों पर राजर्षि राज वर्मा ने यात्राएं की, जो अपने आप में एक अलग अनुभव था। क्योंकि कल राज मिश्र भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ और कुशल राजनेता तो माने जाते थे ही, इसके अलावा राज्यपाल पद पर नियुक्ति के दौरान विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कार्य राज्यपाल की अंतिम अनुमति मिलने के बाद ही संपादित हुआ करते थे। इसलिए जब तक राज्यपाल के एडीसी रहे, तब तक रोजाना विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट लोगों और राजनेताओं के आने-जाने का सिलसिला राज भवन में लगा रहता था। जिसकी वजह से विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों से भी मिलने का इनका अपना एक अलग अनुभव रहा, जो किसी भी इंसान के लिए बेहतर भविष्य बनाने में काफी मदद करता है। इसलिए राज्यपाल के एडीसी पद पर रहने के दौरान भी भले ही यहां पर पुलिस से डिफरेंट काम रहा हो, लेकिन राजभवन में नियुक्ति के दौरान इन्हें जो नॉलेज और जिन विशिष्ट व्यक्तियों से इनकी मुलाकात हुई, वे सभी मुलाकातें और अनुभव राजर्षि राज वर्मा की पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने में काफी सहायक साबित हो रहे हैं। इसलिए राज भवन में हुई पोस्टिंग को भी राजर्षि राज वर्मा काफी महत्वपूर्ण मानते हैं।

सालों से वकीलों के कुनबे में मानवता की मिसाल बने सीनियर एडवोकेट "मोहन कुड़ी"

पेशेवर वकीलों की बड़ी भीड़ में गरीब पक्षकारों को न्याय दिलाने में निभा रहे अग्रणी भूमिका, वकालत के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों के कार्यों में भी सालों से निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका, जाट समाज के विकास और कल्याण में भी हमेशा रहे आगे, अपने अब तक के करीब 38 साल के वकालत के कार्य में हजारों मुकदमों की प्रभावी तरीके से कर चुके हैं पैरवी और अनेकों लोगों को दिलवा चुके हैं इंसान, जयपुर जिले के मनोहरपुर शाहपुरा और आसपास के इलाकों में सरकारी स्कूलों में और अन्य सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में किए गए कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में है काफी पॉपुलर।



जयपुर। प्रदेश के प्रमुख सीनियर वकीलों में शामिल मोहन कुड़ी की गिनती उन वकीलों में होती है, जो पैसों की खनक के लिए नहीं, बल्कि पैसों की कमाई से ऊपर उठकर पीड़ित व्यक्ति को राहत पहुंचाने और उसके कष्ट-तकलीफ को दूर करने के लिए उसकी प्रभावी पैरवी करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जिन्हें पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने से वास्ता रखते हैं और मानवता को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में अपना खुद का एक अलग मुकाम हासिल किया है। इसीलिए मोहन कुड़ी जितने प्रदेश के वकील समुदाय में अपनी अच्छी पर्सनैलिटी, व्यवहार, वर्किंग स्टाइल और बोलचाल से पॉपुलर हैं, उतने ही आम लोगों में एक बेहतर संवेदनशील मानवीय इंसान के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम सुनकर ही लोग इंसान के लिए दौड़े चले आते हैं। पिछले करीब 38 साल के वकालत के इस कार्य में मोहन कुड़ी ने सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू संबंधी हजारों मामलों में प्रभावी पैरवी करके पीड़ितों को इंसान दिलवाया है। जिसमें कई पीड़ित तो ऐसे हैं, जिनकी जेब में केस लड़ने के लिए एक पैसा तक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी

कुड़ी ने उन्हें निराश नहीं होने दिया और कई बार तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके पीड़ित को हर तरह से मदद पहुंचाई। इसीलिए मोहन कुड़ी को वकीलों के इस बड़े समुदाय में मानवता की एक बड़ी मिसाल के रूप में माना जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों और किसानों के लिए हमदर्द वकील के रूप में माने जाते हैं मोहन कुड़ी



जानकारी के अनुसार, मोहन कुड़ी का जन्म जयपुर जिले के मनोहरपुर कस्बे में कुड़ी की ढाणी में एक जाट किसान के घर में हुआ था। इसलिए किसान परिवार की लाइफ स्टाइल और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को बचपन में ही महसूस कर लिया था, जो आज भी कुड़ी के दिल में वैसी की वैसी ही विद्यमान है। आज भी कुड़ी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इंसान के लिए अपने घर और ऑफिस आने वाले फरियादी की पहले पीड़ा को सुनते हैं, उसके केस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अपनी ओर से कभी भी केस लड़ने के लिए फीस के मामले में बात नहीं करते। अगर कोई इनके यहां खाली जेब आकर भी न्याय दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो उसे भी उतना ही आदर और सम्मान देते हैं जितना फीस लेने वालों का करते हैं। और गरीब, मजदूर और किसान के केस की प्रभावी तरीके से पैरवी करके उसे इंसान दिला कर ही दम भरते हैं। इसलिए इनके इस मानवीय स्वभाव को देखकर उनके सहयोगी वकील भी कई बार अचरज में पड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान की आवश्यकता और जरूरत इतनी ज्यादा हो गई है कि चाहे कितना ही पैसा क्यों न कमा ले, फिर भी उसे कम ही लगता है। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, हर व्यक्ति पैसों के पीछे भाग रहा है, लेकिन मोहन कुड़ी ऐसे वकील माने जाते हैं जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके भी गरीब व्यक्ति को हर हाल में इंसान दिलाते हैं। कई बार ऐसा भी

अपने बड़े भाई के कहने पर वकालत का कैरियर चुना

जानकारी के अनुसार, मोहन कुड़ी जब काफी छोटे थे, तब स्कूल की पढ़ाई के लिए अजमेर में अपने बड़े भाई गोपाल चौधरी, जो अजमेर में राजस्थान पुलिस में पोस्टेड थे, उनके पास स्कूल की पढ़ाई के लिए आ गए थे। अजमेर में ही मोहन कुड़ी ने स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की। अजमेर की गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और एलएलबी की डिग्री हासिल की और फिर अजमेर राजस्व मंडल में ही एलएलबी की डिग्री करने के बाद वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। जानकारी के अनुसार, स्कूल की पढ़ाई और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इनके बड़े भाई गोपाल चौधरी ने ही इन्हें वकालत के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित किया। इसलिए अपने बड़े भाई के आग्रह पर मोहन कुड़ी ने वकालत की पढ़ाई कंप्लीट की और फिर अजमेर में ही राजस्व बोर्ड में प्रैक्टिस शुरू की। यहां अजमेर में अपने वकालत के शुरू के सालों में ही मुकदमों की प्रभावी तरीके से पैरवी करके अपने सीनियर वकीलों और जजों को काफी प्रभावित कर लिया था। इसलिए इनके सीनियर वकील यह कहा करते थे कि आगे चलकर मोहन कुड़ी वकालत में काफी नाम कमाएगा। आज उनकी यह भविष्यवाणी काफी सच भी साबित हो रही है, जब मोहन कुड़ी की गिनती श्रेष्ठ और सीनियर वकीलों में होती है।

हुआ जब दूरदराज से मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट में आए व्यक्ति के पास घर जाने के लिए किराए का पैसा तक नहीं होता है, उस समय मोहन कुड़ी मुस्कुराते हुए अपनी जेब से किराए का पैसा निकाल कर पीड़ित व्यक्ति के हाथ में थमाते हैं। इस तरह से मोहन कुड़ी जिस भी व्यक्ति का मुकदमा लड़ते हैं, उसे अपने परिवार का सदस्य ही मान लेते हैं और परिवार के सदस्य की तरह ही उसके साथ रिएक्ट करते हैं। इस तरह की विशेष खासियत आजकल बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है।

"जंगल में मोर नाचा किसने देखा" वकालत के क्षेत्र में मोहन कुड़ी का "अजमेर टू जयपुर" का शानदार सफर



जानकारी के अनुसार, 90 के दशक के शुरू के सालों में मोहन कुड़ी अपने वकालत के क्षेत्र में अजमेर राजस्व मंडल, सिविल कोर्ट इत्यादि में मुकदमों की अपनी प्रभावी पैरवी से कानून व्यवस्था से जुड़े लोगों को काफी प्रभावित कर रहे थे। इसलिए उस समय न्याय व्यवस्था से जुड़े जो लोग इनके साथ काम कर रहे थे, वे सब इनकी प्रतिभा और प्रैक्टिस करने के तरीकों से प्रभावित होकर इन्हें अजमेर की जगह जयपुर में वकालत की प्रैक्टिस करने की सलाह दी और कहा कि जयपुर में अगर आप अजमेर की तरह वकालत के क्षेत्र में काम करोगे तो आपका करियर और बुलंद होगा, क्योंकि जंगल में मोर नाचता है तो उसको कोई नहीं देखता, इसलिए आपको जयपुर कार्यक्षेत्र चुनना चाहिए। इसके बाद वर्ष 1994 में मोहन कुड़ी अजमेर छोड़कर जयपुर आ गए और फिर यहीं पर सिविल, क्रिमिनल और राजस्व संबंधी मुकदमों की प्रभावी तरीके से पैरवी करने लगे। छोटी-बड़ी अदालतों के साथ आज राजस्थान हाई कोर्ट में भी इनका काफी बड़ा नाम है, क्योंकि इन्होंने अब तक हजारों की संख्या में विभिन्न तरह के मुकदमे लड़े हैं, जिनमें इन्हें बहुत ही अच्छी सफलता भी मिली। इसीलिए आज जयपुर में इनका कार्य क्षेत्र काफी बड़ा हो गया है, लेकिन इन्हीं की तरह इनके पुत्र रोहन कुमार ने भी बहुत ही कम समय में श्रेष्ठ वकीलों में अपना नाम शामिल करवा लिया है। अपने पिता की छत्रछाया में रोहन कुमार अपने पिता के कार्य क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ-साथ मोहन कुड़ी की बेटी कनिका भी वकालत की दुनिया में अपनी प्रभावी

प्रदेश के जाट समाज के सम्मानित व्यक्तियों में माने जाते हैं मोहन कुड़ी

जाट समाज से ताल्लुक रखने वाले मोहन कुड़ी राजस्थान के जाट समाज में काफी सम्मानित व्यक्तियों में माने जाते हैं। जाट समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि क्षेत्र से जुड़े सभी तरह के कार्यों में मोहन कुड़ी हमेशा आगे रहते हैं। अगर जाट समाज से जुड़ा कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन हो, या फिर जाट समाज के हितों की रक्षा से जुड़ा कोई मामला कोर्ट में लंबित हो, या फिर जाट समाज की ओर से मंदिर, धर्मशाला इत्यादि का निर्माण करने की बात हो, हर जगह समाज के हर काम में मोहन कुड़ी सबसे आगे नजर आते हैं। इसीलिए राजस्थान के जाट समाज में इन्हें काफी सम्मान की निगाह से देखा जाता है। जाट समाज की ओर से प्रदेश भर में जगह-जगह प्रमुख तेजाजी महाराज के लिए आयोजित होने वाली धार्मिक यात्राएं, जुलूस इत्यादि के आयोजन में हमेशा बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। नागौर के खरनाल इत्यादि कई जगह पर तेजाजी मंदिर के लिए धार्मिक यात्राओं का आयोजन मोहन कुड़ी ने खुद अपने स्तर पर करवाया। इसलिए जाट समाज के हितों की रक्षा के लिए और जाट समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जब भी जाट समाज की ओर से कोई बड़ा मंच सजाया जाता है, तो उसमें मोहन कुड़ी हमेशा सबसे आगे नजर आते हैं। इसीलिए जाट समाज के श्रेष्ठ और सम्मानित व्यक्तियों में मोहन कुड़ी का नाम भी काफी आदर से लिया जाता है।

पैरवी से तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसलिए मोहन कुड़ी अब अपने पुत्र, बेटी के साथ अपने एडवोकेट दामाद को साथ लेकर जयपुर में वकालत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में स्थापित हो गए हैं। अपने परिवार के सदस्यों को वकालत के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए देखकर मोहन कुड़ी काफी खुश और संतुष्ट हैं, तथा अपने बच्चों को भी गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा इंसाफ दिलाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसीलिए अजमेर में जो वकील इनके साथ वकालत किया करते थे, आज जब वे मोहन कुड़ी से मिलते हैं, तो अपना वह कथन इन्हें याद दिलाते हैं जब उन्होंने मोहन कुड़ी से यह कहा था, 'जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा'।

राजनीति में जाना पसंद नहीं, अपनी फैमिली की प्राइवेट और फैमिली को लेकर हमेशा संवेदनशील रहे हैं मोहन कुड़ी



जयपुर टाइम्स हमेशा ही उन लोगों की जीवनी को प्रकाशित करता रहा है जो लोगों के लिए प्रेरणा बने। इसीलिए जयपुर टाइम्स ने जब सीनियर एडवोकेट मोहन कुड़ी के जीवन के बारे में स्टडी की, तो जयपुर के वकीलों से और इनके आसपास रहने वाले लोगों से तथा न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों से इनके बारे में बातचीत की गई, तो हर किसी ने मोहन कुड़ी की प्रशंसा की। मोहन कुड़ी की मानवता के चर्चे हर किसी के मुंह से सुने गए। इसीलिए जयपुर टाइम्स ने जब मोहन कुड़ी से फोन से बातचीत की और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी लोकप्रियता को लेकर जब यह सवाल पूछा गया कि आप राजनीति में क्यों नहीं आते, आपकी लोकप्रियता ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है, तो मोहन कुड़ी ने साफ कह दिया कि इस स्टेज पर आकर वे राजनीति में जाना पसंद नहीं करते। राजनीति में जाने के लिए कभी भी उनके मन में बात नहीं आई। अपने मन की संतुष्टि और दिल की आवाज पर जितना हो सके उतना जरूरतमंद लोगों के लिए मुकदमे लड़ते हैं, और जितना हो सके उतना सरकारी स्कूलों और अन्य सामाजिक सरोकारों के कार्यों में सहयोग दे देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनका राजनीति में जाने का कोई इरादा है। उन्होंने कहा कि वह अपनी और अपनी फैमिली की प्राइवेट को लेकर हमेशा संवेदनशील रहते हैं। खुद की प्राइवेट बनी रहे और उनकी फैमिली उनका पहला प्यार है। फैमिली से जुड़े प्रत्येक सदस्य के परफॉर्मेंस और व्यवहार से काफी खुश हैं। फैमिली के साथ खूब एंजॉय करते हैं, वकालत को इंजॉय करते हैं और गरीबों और बेजुबान पशुओं के लिए जितना हो सके उतनी मदद किया करते हैं, इसी में बड़ा आनंद आता है। इसलिए राजनीति में जाने का ना तो पहले कोई इरादा था और ना ही

निचली अदालतों के सुपरविजन के लिए कुछ विशेष प्रबंध करने की जरूरत

जयपुर टाइम्स के सवाल के जवाब में सीनियर एडवोकेट मोहन कुड़ी ने कहा कि यह सही है कि प्रदेश में लंबित मुकदमों की संख्या बहुत ज्यादा है और मुकदमों का निस्तारण होने में भी काफी समय लगता है, इसके लिए कुछ विशेष प्रबंध करने की भी जरूरत है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि लंबित मामलों में कई मामले ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं, जिनकी सिर्फ कोर्ट में तारीख पड़ती है, लेकिन तारीख के दिन इस तरह के मामलों में कुछ भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सालों से चल रहे मामलों में पक्षकार ही नहीं आते। ऐसे में यह मामले लंबित मामलों में जुड़ जाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इस तरह के मामले पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। इसी तरह से एडीजे कोर्ट के सुपरविजन के लिए भी कुछ और आगे सोचना होगा। इसके लिए अगर किसी हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति करके उसके अधीन चार-पांच एडीजे कोर्ट की सुपरविजन की जिम्मेदारी दे देने से एडीजे कोर्ट की वर्किंग स्टाइल और कार्य क्षमता में बदलाव आने वाला नहीं है, इसके लिए कुछ और बेहतर रास्ते निकालने होंगे। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि कई एडीजे कोर्ट में सुनवाई के लिए ज्यादा मुकदमे नहीं हैं, कई जगह तो 50 मुकदमे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन कोर्ट में कई मामले सालों तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। उनकी तारीख पर तारीख डालकर आगे बढ़ाया जाता रहा है, इसलिए निचली अदालतों के सुपरविजन के तौर-तरीकों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है।

अब है। ईश्वर की कृपा से सब कुछ आनंद से चल रहा है। अपने एडवोकेट बेटे और एडवोकेट बेटी तथा पत्नी से भी काफी खुश और प्रभावित हैं। इनकी बेटी कनिका ने पहले एलएलबी की डिग्री हासिल की, बाद में एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद लंदन में जाकर बिजनेस किया। लेकिन दिल्ली निवासी एडवोकेट से शादी होने के बाद कनिका अब हमेशा-हमेशा के लिए जयपुर शिफ्ट हो गई हैं, और अपने पति, भाई और पिता के साथ वकालत के प्रोफेशन में अपने करियर को गति दे रही हैं। इसलिए अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को देखकर मोहन कुड़ी ईश्वर को हमेशा शुक्रिया अदा करते रहते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि अपने 62 साल के जीवन में मोहन कुड़ी को अनेक गरीब लोगों की दुआएं भी मिली हैं, क्योंकि इन्होंने सालों से गरीब लोगों के मुकदमे लड़कर उन्हें इंसाफ दिलाया और सामाजिक जीवन में हमेशा जरूरतमंद लोगों की सेवा करते रहे हैं। शायद इसी वजह से इनकी फैमिली गरीबों की दुआओं से खुशहाल और आबाद है।



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी जी
व पूर्व प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री जी
की जयंती पर शत-शत नमन



2 अक्टूबर 2026

राजस्थान संवाद

“महात्मा गांधी जी का जीवन राष्ट्रसेवा, सादगी और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणादायी मिसाल है। उनके आदर्श आज भी हमें स्वच्छ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं।”

“लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन सादगी, त्याग और राष्ट्रसेवा का प्रतीक है। उनका अमर मंत्र ‘जय जवान-जय किसान’ आज भी हमें देशहित में कर्म और समर्पण की प्रेरणा देता है।”

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

CAMBRIDGE SR. SEC. SCHOOL

Admission Open 2026-27



प्रवेश सत्र 2026-27 से

विद्यालय परिवार की तरफ से विशेष योजना का शुभारंभ

25 प्रतिशत निःशुल्क (RTE) के
अलावा 25 प्रतिशत और अतिरिक्त
आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को
ट्यूशन फीस फ्री करने का लिया निर्णय

9 C-586,587, 588, 589, 4C SCHEME, NEW LOHA MANDI ROAD, JAIPUR

7230022801, 9983322224

जयपुर टाइम्स

(जयपुर एवं चूरु से एक साथ प्रकाशित)

[illegible]

प्रधान कार्यालय- सी 588, 4सी स्कीम, न्यू लोहा मण्डी रोड, रोड नं. 14, सीकर रोड, जयपुर (राजस्थान)